



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 63]

नई दिल्ली बुधवार, मार्च 17, 1976/फाल्गुन 27, 1897

No. 63]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1976/PHALGUNA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अंगण संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

बजट 1976-77

वित्त मंत्री का भाषण

15 मार्च, 1976

महोदय,

1.1. यह मेरा सीमांत कि एक बार फिर मैं इस महान सदन के सम्मुख बजट पेश कर रहा ।

1.2. पिछले वर्ष जब मैंने 1975-76 के लिए बजट प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी तब उसमें अर्थ व्यवस्था में स्थायित्व लाने और उसे पुष्ट बनाने पर जोर दिया गया था । उस समय अर्थव्यवस्था स्फीति के कठिन दौर से निपट कर पुनः शक्ति ग्रहण कर रही थी, और कृषि की उत्पात काई ज्यादा सुरक्षित नहीं थी ।

1.3. इस वर्ष स्थिति कई दृष्टियों से बदल चुकी है जो एक बड़ी और गतिशील नेतृत्व का परिणाम है । नए आर्थिक कार्यक्रम ने हमारे आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन

और निष्ठा की अपूर्व भावना का संचार कर दिया है। परिस्थितियों के सुधार जाने का लाभ उठाते हुए, 1975-76 के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और अधिक पूँजी लगाने की स्वीकृति दी गई और इस समय हमारा देश समृद्धि की ओर काफी आगे तक बढ़ने के लिए सन्नद्ध है। मैं इस अवसर का प्रयोग विकास की गति में और अधिक तेजी लाने और अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ इसका बरीरा प्रस्तुत करूँगा लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को यदि आरम्भ में ही यह बता दिया जाए कि 1976-77 के लिए आयोजना परिव्यय में 7852 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो 1975-76 की तुलना में 31.6 प्रतिशत ज्यादा है तो उन्हें प्रसन्नता ही होगी। जब से हमारे देश में आयोजनाओं का दौर शुरू हुआ है तब से लेकर किसी भी वर्ष में इतनी ज्यादा रकम विकास परिव्यय के लिए नहीं रखी गई।

1.4. इस बजट में, इस प्रकार, मुख्यतः तेजी से सृद्धि करने पर बल दिया गया है। लेकिन स्थायित्व का तत्व महत्वपूर्ण बना रहेगा। हमारे चारों ओर जाँचें देश हैं वह कहीं तो स्फीति से बुरी तरह पीड़ित हैं और कहीं पर मंदी की स्थिति छाई हुई है। विश्वयुद्ध के बाद पहली बार 1975 में विश्वव्यापार काफी ज्यादा गिर गया। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों के यहाँ आर्थिक कार्यकलाप के स्तर के गिरने के साथ साथ हुआ। हालांकि कुछ देशों की हालत सुचारु रही है लेकिन यह अब भी पतली ही है। स्फीति की आधी अनेक देशों को उजाड़ रही है। जो विकासशील देश तेल का निर्यात नहीं करते उनका भुगतान घटाने की स्थिति पर इन सब का दबाव पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था हालांकि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक सुदृढ़ है लेकिन वह इन दबावों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इसकी व्यवस्था को ठोस बनाये रखते के लिए हम सबको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।

1.5. चालू वर्ष में भारत के आर्थिक कार्य परिणाम हम सबके लिए न केवल सन्तोषप्रद बल्कि निश्चय हैं। गर्व की बात रहे हैं। सभी क्षेत्रों में उत्पादन में सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, खान उद्योग, विद्युत, परिवहन आदि क्षेत्र में हमें अपूर्व सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसे कीमतों में बराबर कमी लाते रहने में सफलता प्राप्त हुई, यह कमी अक्टूबर, 1974 से शुरू हुई। 21 फरवरी, 1976 को समाप्त सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक गिर कर 288 रह गया और यह एक सात पहले का सूचक अंक की तुलना में लगभग 7.3 प्रतिशत कम है, पिछले साल इन दिनों उससे पिछले साल की तुलना में कीमत 12.5 प्रतिशत ज्यादा थी। उपभोक्ता कीमतों भी गिरने लगी हैं। जनवरी 1976 में अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार उपभोक्ता कीमतों का सूचक अंक जनवरी 1975 के 326 के सूचक अंक की तुलना में 8.6 प्रतिशत कम था अर्थात् यह 298 था। मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि उपभोक्ता कीमतों के सूचक अंकों का 12 महीनों का औसत गिर कर 368.6 रह गया है। कीमतों के विरुद्ध संघर्ष करने में हमें जो सफलता मिली है उससे निराशा और सन्देश के वातावरण को दूर करने में सहायता मिली है जो 1973-74 में छाया हुआ था। अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमने जिस तरीके से इस संघर्ष में विजय प्राप्त की है वह हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत दृढ़ता और परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने की क्षमता का सजीव प्रमाण है।

1.6. पिछले वर्ष मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान कीमतों को बढ़ने से रोकने की ओर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की सृद्धि को तेज करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत की ओर भी दिलाया था। इसलिए यह विशेष संतोष की बात है कि वर्ष के दौरान कीमतों के रुख में अनुकूल परिवर्तन होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सृद्धि की दर भी अच्छी रही है। मौजूदा

संकेतों के आधार पर राष्ट्रीय आय निम्न रूप में 1975-76 में लगभग 5.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी। यह सफलता सरकार द्वारा कारखानों और खेतों के उत्पादन में वृद्धि करने में आने वाली विभिन्न रुकावटों को दृढ़ निश्चय के साथ दूर करने में की गई अनेक कोशिशों के कारण है। खासतौर से उन कोशिशों के कारण जो जुलाई, 1975 के बाद नए आर्थिक कार्यक्रम को अभियान के रूप में शुरू करने के बाद की गई। अच्छे बीज, सिंचाई और उर्वरकों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए पुरजोर कोशिशों के परिणामस्वरूप कृषि में विकास की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। उद्योग में काम आने वाली विद्युत, कोयला और इस्पात जैसी महत्वपूर्ण चीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो सोद्देश्य प्रयास किए गए वह औद्योगिक उत्पादन में और वृद्धि करने की दिशा में शुभ लक्षण हैं। तस्करी और अनधिकृत तरीके से विदेशी मुद्रा के लेनदेन से विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिए की गई कार्रवाई से देश की विदेशी भुगतान स्थिति पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। इस तथ्य से कि चालू वर्ष के अंत तक सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के पास 110 लाख टन तक अनाज का भंडार हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को पर्याप्त शक्ति मिलती है। कुल मिला कर भारतीय आर्थिक स्थिति का कोई भी तटस्थ प्रेक्षक आर्थिक अनुशासन के कड़ाई के साथ लागू करने से होने वाले लाभ को आसानी से हृदयंगम कर सकता है। 1975-76 में अर्थ व्यवस्था की प्रगति के अत्यन्त सन्तोषजनक होने से अब हम आने वाले वर्ष में सामाजिक और आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए और ज्यादा कोशिशें कर सकते हैं।

II

2.1. आर्थिक सबृद्धि की दर में निरन्तर वृद्धि करते रहने की बुनियादी शर्त यह है कि अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में पर्याप्त पूंजी लगाई जाए। इसी उद्देश्य के अनुसरण में 1975-76 में वार्षिक आयोजना के परिचय में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सौभाग्य से इस समय हमारी खाली स्थिति और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की स्थिति ऐसी है कि हम कीमतों की स्थिरता को छोड़े बिना 1976-77 के लिए परिचय में और अधिक वृद्धि करने की योजना बना सकते हैं। स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी को इस दिशा में एक प्रमुख भूमिका अदा करनी है। इसलिए 1976-77 के बजट में मेरी सबसे पहली कोशिश यह है कि कार्य निष्पादन के लिए उपलब्ध संगठनात्मक क्षमता के अनुरूप पूंजी निवेश में यथासंभव अधिक से अधिक वृद्धि की जाए। इस प्रकार जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं 1976-77 की वार्षिक आयोजना का 7852 करोड़ रुपये का परिचय 1975-76 की वार्षिक आयोजना के परिचय की तुलना में 31.6 प्रतिशत अधिक है।

2.2. मुझे विश्वास है कि आयोजना परिचय में परिकल्पित वृद्धि से कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि यह कठोर आर्थिक अनुशासन के आधार पर ही संभव है। ऊंची कीमतों के खिलाफ संघर्ष में सफलता सिर्फ इसीलिए मिली कि देश ने उत्साहपूर्वक आर्थिक अनुशासन को अपनाया जिसकी कि बड़ी जरूरत थी। इस समय कीमतों में स्थिरता आ जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आर्थिक अनुशासन के लागू करने में ढील दी जा सकती है। कीमतों में स्थिरता को समाज के सभी वर्गों के सोद्देश्य सहयोग से बनाए रखना पड़ेगा। यह मान बैठना कि कीमतों में स्थिरता अपने आप बनी रहेगी एक भयंकर भूल होगी। अगर हम चौकस नहीं रहे तो कीमतों में वृद्धि का भयंकर दौर फिर से शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जितनी सीमा तक संभव हो उतनी सीमा तक अधिक से अधिक वास्तविक बचतें कर योजना बद्ध तरीके से पूंजी निवेश में वृद्धि के लिए धन जुड़ाया जाए। इसका अर्थ यह भी है कि अर्थव्यवस्था में सबृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए समाज को

चाहिए कि वह इस समय अपनी खपत में स्वेच्छापूर्वक कमी करने के लिए राजी हो। हमारी आर्थिक नीतियों को पुंजी निवेश और बचतों में संवृद्धि करने में आवश्यक रूप से सहायक होना होगा। मैं अपने भाषण में बाद में यह बताऊंगा कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता देने के लिए हमारी कराधान की प्रणाली को किस प्रकार ढाला जा रहा है। इसके साथ ही गैर-विकासत्मक खर्च की वृद्धि में कटौती करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। आपात-स्थिति की घोषणा के बाद अनुशासन में सामान्य रूप से जो सुधार आया है उससे सरकार के प्रशासन की क्षमता में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि ओवर टाइटन पर जो खर्च होता था उसमें काफी बचत भी हुई है। हमें इस गति को बनाए रखना है। खालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और इनके उत्पादन में संवृद्धि की दर 15 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हमें इसमें लगातार वृद्धि करते रहना है जिससे पिछले वर्षों में इन में जो भारी पूंजी लगाई गई थी उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र को भीतिक और आर्थिक साधनों के दस्तेमाल में भारी अनुशासन की जरूरत को, जिससे बचा नहीं जा सकता, स्वीकार करना चाहिए। ऋण संबंधी नीतियों को बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना होगा। लेकिन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण के प्रयोग की युक्तिसंगत व्यवस्था का निर्माण करने के बुनियादी उद्देश्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण देने की रीति भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार होनी चाहिए। सर्वसाधारण की खपत में आने वाली चीजों की खरीद और सार्वजनिक वितरण के कारगर प्रबंध भी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के आवश्यक अंग होने चाहिए।

2. 3. पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में 1975-76 के लिए बजट प्रस्तावों में क्षेत्रों के आधार पर निहित स्थूल प्राथमिकताओं का उल्लेख किया था। यह प्राथमिकताएं आज भी प्रामाणिक हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि हमारे जैसे देश में जनता की गरीबी को गांवों में फ़ैली गरीबी के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करके ही दूर किया जा सकता है, कोई ज्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी हमें अक्सर याद दिलाया करते थे, भारत गांवों में बसता है। इसका अर्थ यह है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि विकास के कार्यक्रमों को और इसके सहायक अन्य क्षेत्रों जैसे विद्युत, सिंचाई, उर्वरक और हानिकार कीड़ों मकोड़ों का नाश करने वाली दवाओं के क्षेत्रों को दी जाती रहनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि गांवों में फ़ैली गरीबी और पिछड़ेपन के खिलाफ़ कारगर लड़ाई की योजना ग्राम विकास के ऐसे समन्वित कार्यक्रम के ढांचे के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है जो स्थानीय आवश्यकताओं, प्राप्त साधनों और संभावनाओं की विस्तृत जानकारी पर आधारित हो। हमारा ध्यान विदेशों से उद्योग की अधिक से अधिक वस्तुओं के आयात करने के बजाय स्थानीय उपलब्ध साधनों का उपयोग करने पर होना चाहिए जिनमें स्थानीय जनशक्ति भी शामिल है। हमें जिला स्तर की प्रचालन आयोगों पर तैयार करनी होंगी। इनमें प्रत्येक क्षेत्र की सटीक और अलग-अलग आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, प्राकृतिक साधनों का तुरन्त व्यापक सर्वेक्षण करना जरूरी हो गया है। हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन प्रदान करने के लिए, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरा पूरा लाभ उठाना होगा।

2. 4. कुल मिलाकर उद्देश्य यह होना चाहिए कि एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाय, जिससे दुहरे लक्ष्य की अर्थात् उपलब्ध जनशक्ति को उत्पादक रोजगार प्रदान करने और हमारे सभी प्राकृतिक साधनों का वैज्ञानिक उपयोग करने की पूर्ति हो सके। यह सच है कि ऐसी विकास नीति को एक दिन में ही लागू नहीं किया जा सकता। प्रचालन

के वास्तविक कार्यक्रमों का निर्माण करने से पहले काफ़ी तैयारी करने की आवश्यकता है। इसमें इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि बदलती हुई ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तन और संशोधन किए जा सकें। सभ्यतम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयत्नों के लिए, 1976-77 के केन्द्रीय बजट में 15 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। मुझे आशा है कि हमें 1976-77 में जो अनुभव प्राप्त होंगे उसके आधार पर हम इस कार्यक्रम के क्षेत्र का उत्तरोत्तर अधिक विस्तार कर सकेंगे।

2. 5. आधुनिक वैज्ञानिक और कृषि और उद्योग के बीच बड़ा निकट संबंध है। कृषि की प्रगति बुनियादी तौर से नए से नए बीजों, सिंचाई, विद्युत और उर्वरकों जैसी चीजों की सप्लाई पर निर्भर करती है। चालू वर्ष में राष्ट्रीय बीज परियोजना में सन्तोषजनक प्रगति हुई है और इस समय अच्छी किस्म के बीजों की कोई कमी नहीं है। हाल में अन्तर्राष्ट्रीय नदी विवादों को जिस तेजी से हल किया गया है उससे देश के विशाल जल साधनों के अधिक तेज और युक्तिसंगत विकास का काम निश्चय ही आसान हो जाएगा।

2. 6. पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि विदेशों से उर्वरकों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने में भारी जोखिम रहता है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने उर्वरक कार्यक्रम को जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ाएं। मुझे इस बात से बड़ा सन्तोष होता है कि चालू वर्ष में देश में उर्वरक क्षमता के उपयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है। आज यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हमारे देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

2. 7. सरकार ने अभी हाल ही में उर्वरकों की कीमतों की जांच की है यह जांच इस बात का सुनिश्चय करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए की गई है कि खेती में उत्पादन और लागत का अनुपात इतना अवश्य होना चाहिए जिससे इस काम में और अधिक पूंजी लगाने को बढ़ावा मिले और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि हो। माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि यूरिया की कीमत को 1850 रुपए प्रति टन से घटा कर 1750 रुपए प्रति टन करने का फैसला किया गया है। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। फास्फोटी और पोटाशो उर्वरकों की खपत वांछित स्तर से कम है। इसलिए सरकार ने देश में उत्पादित सभी फास्फोटी उर्वरकों और कुछ चुनी हुई किस्मों के आयात किए गए फास्फोटी उर्वरकों की कीमतों को 1250 रुपए पौ० ओ० के प्रति टन के हिसाब से घटाने का निर्णय किया है। म्यूरिएट आफ पोटाश की कीमत को भी 1085 रुपए प्रति टन से घटा कर 900 रुपए प्रति टन किया जाएगा। मैं आयात किए गए राक फास्फेटों से संबंधित प्रस्तावों की चर्चा बाद में करूंगा। मुझे विश्वास है कि उर्वरकों की कीमतें घटा देने से उनकी खपत बढ़ जाएगी।

2. 8. आधुनिक कृषि के लिए ऋण की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक बैंकों ने राष्ट्रीकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों का भारी विस्तार किया है। लेकिन अभी भी, जितना ऋण मिल सकता है और जितना अवैध है उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को कुछ हद तक अब नए खोलें गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पूरा किए जाने की कोशिश की गई है। यह बैंक गांव की जनता के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देंगे।

2. 9. देश की अर्थव्यवस्था, विशेषतः उसके औद्योगिक आधार के विकास के लिए विद्युत, कोयले, तेल और लोहे तथा हस्पात जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की ज़रूरत पर

जितना भी जोर दिया जाए उतना कम है । 1975-76 में इन वस्तुओं के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई । अनुमान है कि 1975-76 में कोयले का उत्पादन 980 लाख टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा । विद्युत के उत्पादन में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी । फिर भी और अधिक तेजी से आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है । सुपर थर्मल पावर स्टेशनों की स्थापना, देश को विद्युत की निरन्तर बनी रहने वाली कमी से मुक्त करने के कार्यक्रम का एक आवश्यक आधार है । तट पर और तट से दूर दोनों स्थानों पर तेल की खोज करने के कार्यक्रमों में काफी तेजी आई है और मौजूदा संकेतों के अनुसार मध्यम अवधि के लिए सभावनाएं काफी अधिक अनुकूल प्रतीत होती हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी वर्षों में उत्पादन में वृद्धि होती रहे हमें इन सभी उद्योगों के लिए पर्याप्त निवेश-योग्य साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए । 1976-77 के बजट में ठीक यही किया जा रहा है ।

2. 10. राष्ट्रीय पूंजी निवेश नीति की योजना बनाते समय हमारे लिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि गैर-सरकारी पूंजी निवेश का स्तर और क्षेत्रों के आधार पर उसका विभाजन हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो । मैं यह मानता हूँ कि हाल के वर्षों में कुछ प्रमुख उद्योगों में जो पूंजी-निवेश किया गया वह उतना नहीं था जितना कि होना चाहिए था । सरकार ने कुछ प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की लाभकारिता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं । कीमत निर्धारण करने की नीति को अधिक उदार बनाया गया है । कुछ मामलों में कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है और कुछ अन्य मामलों में दोहरी कीमतों की प्रणाली अपनाई गई है ताकि पूंजी लगाने वालों को उचित लाभ हो और इसके साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के प्रयोक्ताओं को, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने से बचाया जाए । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तेजी से बदलने वाली इस दुनिया में कीमत निर्धारण करने की हमारी नीतियां में इतनी गुंजाइश जरूर रहनी चाहिए जिसकी जरूरत भी है, कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित किया जा सके ।

2. 11. मुझे मालूम है कि हाल के वर्षों में पूंजी लागत में भारी वृद्धि हुई है जिससे नए पूंजी-निवेश की लाभकारिता पर प्रभाव पड़ा है । कुछ वर्ष पहले जब विकास छूट वापस लेने का फैसला किया गया था, तब इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था । मैं स्वीकार करता हूँ कि पूंजी लागत में वृद्धि होने से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वे वास्तविक हैं और कारगर ढंग से उनका समाधान करने के तरीके ढूंढने चाहिए । इस बजट में ऐसा ही करने की कोशिश की जाएगी ।

2. 12. मौजूदा पूंजी निर्गम (छूट) आदेश के अन्तर्गत, केवल बोनस निर्गमों और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रणाली अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड कम्पनियों को पूंजी जारी करने के लिए पूंजी निर्गम नियंत्रक की विशिष्ट स्वीकृति लेनी जरूरी होती है । अन्य निर्गमों के मामलों में, यदि बारह महीने की अवधि में निर्गम की राशि 25 लाख रुपये से अधिक हो तो कम्पनियों के लिए केवल यही जरूरी होता है कि वे नियंत्रक को प्रस्तावों का विवरण भेज दें । अब इस सीमा को बढ़ा कर 50 लाख रुपये कर देने का प्रस्ताव है । लेकिन बोनस निर्गमों या एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रणाली अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले निर्गमों से संबंधित विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

2. 13. हमारे लिए यह विशेष चिन्ता का विषय रहा है कि सूती कपड़ा, जूट की विनिर्मित वस्तुओं और चीनी जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पर्याप्त साधन नहीं लगाए हैं । ये उद्योग महत्वपूर्ण कृषिजन्य कच्चे माल को प्रोसेस करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में कामगारों को सीधे रोजगार देते हैं । ये उद्योग देश की विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोत हैं । इसके अलावा कपड़ा और

चीनी ग्राम उपयोग की प्रमुख चीजें हैं। इसलिए देश का हित इन उद्योगों के सुचारु संचालन में है। कुछ किस्मों के इंजीनियरिंग उद्योगों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसे समय रहते दूर करना जरूरी है। सीमेंट उद्योग में, “बेट प्रोसेस” के स्थान पर “ड्राई प्रोसेस” को अपनाते से उत्पादन लागत में क़िफायत की जा सकती है। इस लिए एक अन्य बात जिसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए यह है कि इन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए और इन्हें नए सिरे से चलाने के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाए। इस उद्देश्य से, औद्योगिक विकास बैंक के लिए काफी साधनों की व्यवस्था की जा रही है जिससे यह बैंक सावधि ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं के सहयोग से इन उद्योगों के आधुनिकीकरण, नवीकरण और नए सिरे से चलाने की आवश्यकताओं का खर्च पूरा कर सके।

2.14. मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि ग्राम तौर पर किसी उद्योग के संकट-ग्रस्त होने का कारण प्रबन्ध व्यवस्था का कुशल न होना होता है। मैं सोचता हूँ कि विस्तीय संस्थाओं को विन्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों की प्रबन्ध व्यवस्था को कुशल बनाने की सुचारु व्यवस्था का निर्माण भी करना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि चीनी जैसे उद्योगों का सही विकास भन्ने के उत्पादन में वृद्धि की स्थिर दीर्घकालीन नीति के अपनाए जाने पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सूती कपड़ा उद्योग की प्रगति कपास के विकास की सही नीति के निर्माण से जुड़ी हुई है। इसके अलावा, कपड़े सम्बन्धी समन्वित नीति में हथकरघा क्षेत्र की, जो बहुत बड़ी संख्या में गरीब बुनकरों को रोजगार प्रदान करता है, पक्की सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी जरूरी है।

2.15 निस्संदेह यह सच है कि आजकल कुछ उद्योगों को अपनी चीजों की मांग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे आशा है कि 1976-77 के आयोजना परियोजना में परिकल्पित वृद्धि से मौजूदा औद्योगिक क्षमताओं के अधिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। टिकल उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कई उद्योगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि बेरोजगारी को रोकने की दृष्टि से इन उद्योगों को अपनी संक्रमण कालीन समस्याओं को हल करने के लिए सहायता देने की बात में कुछ दम हो सकता है, लेकिन उसका ज़रूदा रहना इस बात से जुड़ा हुआ है कि उनमें अपने क्रियाकलापों में अनेक-रूपता लाने और ऐसी किस्मों की वस्तुओं का उत्पादन करने की कितनी योग्यता है, जिनकी कि मांग देश में बढ़ सकती है।

2.16. देश की विदेशी भुगतान क्षमता के बने रहने की एक आवश्यक शर्त यह है कि निर्यात की मात्रा में 8 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से वृद्धि होती रहे। सरकार ने हाल में निर्यातकर्ताओं के लिए प्रक्रियाओं को और सरल तथा सुविधाओं को और उदार बना दिया है। नकद सहायता देने और शुल्क की वपसी की प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया गया है। हमारे निर्यात की प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करने के लिए नकद सहायता की दरों में उचित संशोधन किए गए हैं। देश में आन्तरिक कीमतों के स्तर में स्थिरता लाने में जो सफलता प्राप्त की है उससे, और देश के अन्दर श्रैता-बाजार के निर्माण से भी हमारी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रतियोगिता-क्षमता बढ़ गई है। इस तथ्य से कि एक ऐसे वर्ष में जब विश्व व्यापार की मात्रा में कमी हुई हो, हमारे निर्यात की मात्रा में 7 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है, इस बात का पता चलता है कि निर्यात संवर्धन के हमारे प्रयत्न अधिकाधिक सफल रहे हैं। मैंने जूट, कपड़े और चीनी उद्योगों के आधुनिकीकरण

के जिन कार्यक्रमों का पहले उल्लेख किया है, उनका उद्देश्य देश के निर्यात में और वृद्धि करना है। हाल में रुपए की विनिमय दर भी पीछे से अग्रसर कर दिया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि रुपए की विनिमय दर का निर्धारण भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के समूह के मूल्यों में होने वाली घटबढ़ को देख कर किया जाए। इसका उद्देश्य प्रभावी विनिमय दरों से मुक्त मुद्राओं के संसार में हमारे विदेशी व्यापार को अधिक स्थिरता प्रदान करना है। देश में अनेक प्रकार के उद्योगों के खुल जाने के कारण भारत के लिए अब यह संभव हो गया है कि वह अपने निर्यात में सफलतापूर्वक वृद्धि करने की पुरजोर कोशिश करे जो पहले करना संभव नहीं था।

2.17. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई है कि व्यापक गरीबी विशाल मानव जाति की निर्यात बन कर नहीं रह सकती। देश ने कृषि विकास के लिए परमाणु उर्जा के उपयोग अंतरिक्ष विषयक खोज और आधुनिक विज्ञान के उपयोग के क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त की है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन की गति को तेज करने की जरूरत है। इस प्रक्रिया के अंग के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आयोजना के अन्तर्गत 1976-77 में 156 करोड़ रुपया रखा जाएगा जो चालू वर्ष के 116 करोड़ रुपए के संभावित व्यय की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है। माननीय सदस्य निस्सन्देह सरकार द्वारा एक अनुसंधान और विकास उपकर लगाने के निर्णय का स्वागत करेंगे जिससे इस प्रकार के उद्यमों के लिए धन जुटाया जा सके। इस संबंध में उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, इसी सत्र में एक विधेयक पेश करेगा।

2.18. हालांकि अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए अधिक उत्पादन करना बहुत जरूरी है फिर भी यह सामाजिक न्याय केवल अधिक उत्पादन करने से ही नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हमारी विकास नीति में समाज के अपेक्षाकृत अधिक कमजोर वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता को महत्व दिया गया है। बीस सूची आर्थिक कार्यक्रम ने इस तरह के कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने की महान आवश्यकता की दिशा में नए सिरे से जागरूकता पदा कर दी है। फालतू जमीन का फिर से वितरण करने, गरीबों को मकान बनाने के लिए जगह देने और खाली पड़ी शहरी जमीन का सामाजिक उपयोग करने के उपायों को कारगर तरीके से क्रियान्वित करने से आय वितरण के ढांचे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। परिवार नियोजन भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है और अब इस पर पहले की अपेक्षा अधिक जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज के उन लोगों के जीवन स्तर और रहन सहन के तरीकों में सुधार लाना है जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुविधाएं प्राप्त हैं। शहरों का यथोचित विकास करने और उनका नवीकरण करने के कार्यक्रम के अंग के रूप में कम आय वाले लोगों के वास्ते मकान बनाने की गति को तेज करने के लिए नए कार्यों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस तरह से विशेष कार्यक्रमों में अभीष्ट सफलता सभी मिलेगी जब ये कार्यक्रम विकास की समेकित नीति के अंग बन जाएंगे।

2.19. सरकार यह महसूस करती है कि यदि विकास की प्रक्रिया की गति तीव्र काली है और आयोजनाओं तथा कार्यक्रमों को सही तरीके से अमल में लाना है तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कुछ बुनियादी फेरबदल करना भी जरूरी है। इस समय मंत्रालयों और विभागों

से बाहर एक अन्य एजेंसी द्वारा हिसाब किताब रखने की जो व्यवस्था है वह कारगर तरीके से वित्तीय प्रबन्ध करने की दिशा में अधिक उपयोगी नहीं है। लेखा और वित्त दोनों को कुल मिलाकर समूचे प्रबन्ध का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और उन्हें परियोजनाओं का चयन करने, रहमें नियंत्रित करने, वास्तविक प्रगति के सदर्भ में खर्च पर नियंत्रण रखने और परिणामों का मूल्यांकन करने के काम में अपेक्षाकृत अधिक सार्थक और कारगर भूमिका अदा करनी चाहिए। लेखाओं को प्रशासनिक मंत्रालयों में मिला देने के उद्देश्य से इन्हें लेखा परीक्षा से अलग कर देने और विभागीय लेखा प्रणाली शुरू करने का विचार है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के लेखाओं को लेखापरीक्षा से अलग करने के काम को पहली अक्टूबर 1976 तक पूरा कर देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस नई स्कीम के अन्तर्गत प्रशासनिक मंत्रालय अदायगियां करने और ठीक समय पर लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें पेश करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। उपर्युक्त सुधार लाने से खर्च की प्रगति की सूचना समय पर प्राप्त करने में सुविधा होगी और इससे खर्च के रख का सही विश्लेषण किया जा सकेगा। इस बात में जरा भी शक नहीं है कि इस तरह से सूचना मिलने पर सही निर्णय लेने तथा जहां आवश्यक हो वहां उपचारात्मक कदम उठाने में बड़ी आसानी होगी। चूंकि यह परिवर्तन भारतीय प्रशासन के इतिहास में बुनियादी और अभूतपूर्व परिवर्तन है इसलिए इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि इस परिवर्तन के दौर में अदायगियों के मामलों में अथवा हिसाब किताब रखने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न होने पाए। निस्संदेह सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत हैं कि राष्ट्रपति ने इन उद्देश्यों को पूरा करने तथा इस बात का सुनिश्चय करने के लिए दो अध्यादेश जारी किए हैं कि सरकार ने जो नई जिम्मेदारियां संभाली हैं उन्हें निभाने के लिये उसे कुशल कर्मचारी उपलब्ध हों। ऐसा करने में हमेशा इस बात की सावधानी बरती जायेगी कि कर्मचारियों को कम से कम कठिनाई हो और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपने संवैधानिक दायित्वों को बिना किसी अडचन के और कारगर तरीके से निभा सकें। सुधार के इस काम में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पूरी तरह से संबद्ध रहे हैं और सभी काम उनके परामर्श से किये गये हैं।

2. 20. सरकार अपने कर्मचारियों के व्यक्तिगत दायों और जनता के साथ लेन-देन करने की कार्य-प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और उसे तबूत बनाने के काम को भी अधिक महत्व देती है। पेंशन, उपदान और सरकारी अधिकारियों के वेतन की निकासी करने की मौजूदा कार्य-प्रणाली की बारीकी से जांच की गई है और पेंशन के कागजात तैयार करने तथा पेंशन और उपदान की मंजूरी देने में जो विलंब होता है उसे दूर करने के लिये कई उपाय किए गए हैं। राजस्वित सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी करने की कार्य-प्रणाली को भी सरल बना दिया गया है। सरकार और उसके कर्मचारियों तथा अन्य नागरिकों के बीच वित्तीय लेन-देन करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं का उपयोग करने का विचार है। मौजूदा कार्य-प्रणाली के मुताबिक आजकल इस तरह के लेन-देन केवल थोड़े से राजकोषों अथवा बैंकों के साथ ही किए जा सकते हैं लेकिन नई व्यवस्था मौजूदा प्रणाली की अपेक्षा काफी सुधरी हुई है।

2. 21. कर वसूल करने, करों की चोरी की रोक थाम करने और अनेक तरीके से विदेशी मुद्रा के अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल पर रोक लगाने की व्यवस्था की त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। आयकर को दरे कम कर देने के बावजूद इस मद के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक रकम प्राप्त होने, स्वेच्छा से अपनी आय और सम्पत्ति प्रकट करने की स्कीम को अनाधारण सक्तता मिलने तथा तत्सहरी के खिलाफ कारगर कदम उठाने के कारण अदृश्य मर्दानों से विदेशी मुद्रा का प्राप में भारी

वृद्धि होने से इस बात का संकेत मिलता है कि कर की वसुली करने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो कदम उठाए गए वे कारगर साबित हुए। मैं इस अवसर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों की सराहना करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

2. 22. मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कर की चोरी तथा काले धन जैसी बुराइयों को केवल प्रशासनिक तंत्रों में कड़ाई ला कर सफलतापूर्वक दूर नहीं किया जा सकता। इस दिशा में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना भी उतना ही जरूरी है कि हमारी आर्थिक नीतियां, जिनमें हमारी राजकोषीय नीतियां भी शामिल हैं, ऐसी होनी चाहिए कि जिनसे कर की चोरी और काले धन की कमाई करने वालों को प्रोत्साहन ही न मिले। सरकार ने इस अभियान के अंग के रूप में आर्थिक शक्ति के और अधिक केन्द्रीकरण को किसी भी तरह का बढ़ावा दिए बिना उन नियंत्रणों को अचूक और सरल बनाने की कोशिश की है जो या तो पुराने पड़ चुके हैं या जो अब कारगर नहीं रहे। विदेशों में रहने वाले गैर-आवासी भारतीयों द्वारा इस देश में विदेशी मुद्रा भेजने की प्रणाली को सरल बनाने तथा उन्हें और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार ने जो कदम अभी हाल ही में उठाए हैं उनका लक्ष्य इसी उद्देश्य को पूरा करना है कि रभा, उक्त कार्यप्रणाली को सरल तथा और अधिक उदार बनाने का काम कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो एक बार में ही पूरी हो जाए। जनता के हित के लिए हमारे विनियमनकारी तंत्र के अंग के रूप में कुछ नियंत्रण हमेशा बने रहेंगे और यह मान कर चलना होगा कि ये नियंत्रण हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। लेकिन, जहां आवश्यक है वहां हमारे नियंत्रण के तंत्रों को अधिक लोचदार बनाने, उनके संचालन में सुधार ला कर अपेक्षाकृत अधिक कारगर बनाने, प्रत्येक नियंत्रण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इनके स्थूल उद्देश्यों के साथ इनका तालमेल बिठाते रहने और इस बात पर बराबर नजर रखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में इन नियंत्रणों से इनमें निहित उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है अथवा इसके स्थान पर कोई और व्यवस्था इससे अच्छी रहेगी या नहीं।

2. 23. मैं सोचता हूँ कि अब तक जो कुछ मैं कह चुका हूँ उससे माननीय सदस्यों को वर्ष 1976-77 के बजट के उद्देश्यों तथा नीतियों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी होगी। इसलिए अब मैं वर्ष 1975-76 के संशोधित अनुमानों का और वर्ष 1976-77 के बजट अनुमानों की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में ब्यौरा पेश कर रहा हूँ।

III

1975-76 के लिए संशोधित अनुमान

3. 1. 1975-76 के लिए मूल बजट में 247 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान किया गया था। किन्तु यह घाटा खर्च में कुछ ऐसी वृद्धि होने के कारण, जो रोक नहीं जा सकती थी, चालू वर्ष के अन्त तक और ज्यादा हो जाएगा। इस अतिरिक्त खर्च के अधिकांश भाग का संबंध सरकार के उस कार्य से है जिसका उद्देश्य आर्थिक संबृद्धि की गति को तेज करना है।

3. 2. अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी की स्थिति बने रहने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि निर्यात में वृद्धि करने के लिए और जोरदार कोशिश की जाए। इससे आशा है कि निर्यात के संवर्धन की स्कीमों पर खर्च मूल बजट अनुमानों में 88 करोड़ रुपए की व्यवस्था की अपेक्षा 71 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा।

3. 3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य परिणामों में भारी सुधार हुआ है लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं खास तौर से राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जिन्होंने इतना उत्पादन नहीं किया कि वह अपनी देनदारियों को पूरा कर सकें। इस कारण से सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को मूल बजट में गैर-आयोजना सहायता देने के लिए रखी गई 170 करोड़ रुपयों की रकम में 210 करोड़ रुपयों की वृद्धि करनी पड़ी।

3. 4. खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होने का लाभ उठा कर सरकार ने पर्याप्त अनाज का सुरक्षित भंडार रखने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन से बजट में भारतीय खाद्य निगम के लिए 130 करोड़ रुपए—100 करोड़ रुपए इक्विटी पूंजी और 30 करोड़ रुपए उधार के रूप में रखे गए हैं। सदन इस बात से सहमत होगा कि यह पूंजी उचित ही लगाई जा रही है।

3. 5. मूल बजट में उर्वरकों की खरीद व बिक्री के लिए 140 करोड़ रुपए रखे गए थे। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है उर्वरकों की पूल कीमतें जुलाई, 1975 और दिसम्बर 1975 में घटानी पड़ीं जिससे इनकी खपत में वृद्धि की जा सके। इस कारण और शुरू में उर्वरकों की कम बिक्री होने तथा रकम की देर में वसूली होने के कारण इस भंड में 173 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि का अनुमान है।

3. 6. रक्षा व्यय 136 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा जो मुख्यतः अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की मंजूरी और राशन व अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि होने के कारण है। सितम्बर 1975 में मंजूर किए गए मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के कारण, जिनके लिए बजट बनते समय कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, खर्च में और भारी वृद्धि हुई है जो संशोधित अनुमानों में अन्य मदों में भी दिखाई देती है।

3. 7. इन देनदारियों के कारण बजट पर जो बोझ पड़ा उसके बावजूद हम ने अपने विकास कार्यों को यथापूर्व बनाए रखा और उन पर खर्च में कोई कमी नहीं आने दी। आयोजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों खासतौर से इस्पात, नौवहन और परिवहन तथा खानों, उर्वरकों, कोयला और विद्युत् के क्षेत्रों में भी पूंजी निवेश में 1975-76 के बजट की अपेक्षा वृद्धि कर दी गई। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर परिव्यय में भी काफी वृद्धि की गई। रेलों के लिए अतिरिक्त रकम रखी गई है जिससे वह अपनी आयोजना के बड़े हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने साधनों की कमी को पूरा कर सकें। यहां मैं रेलों द्वारा माल के ढिबों की और ज्यादा खरीद करने के लिए रखी गई 53 करोड़ रुपए की व्यवस्था का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि इससे इंजीनियरिंग के उद्योग को भी बड़ावा मिलेगा। कुल मिला कर केन्द्रीय आयोजना के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूल बजट में जितनी व्यवस्था की गई थी उससे यह रकम 270 करोड़ रुपए ज्यादा हो जाएगी।

3. 8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए बजट में मूलतः 1054 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी जिसमें सिंचाई और विद्युत् के बुनियादी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पर्याप्त पूंजी लगाने की निश्चित व्यवस्था करने के लिए कुछ ऐसे राज्यों को जिनके पास कम साधन उपलब्ध हैं, 100 करोड़ रुपयों की विशेष सहायता शामिल है। बाद में जब राज्यों के साधनों का मूल्यांकन किया गया तो यह पता चला कि उनमें यह अन्तर जितना सोचा गया था, उससे ज्यादा होगा। इसके परिणामस्वरूप विशेष सहायता की व्यवस्था को बढ़ा कर 175 करोड़ रुपए कर दिया गया। नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद राज्यों को 85 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया गया जिससे राज्य सिंचाई और विद्युत् की चुनी हुई परियोजनाओं पर परिव्यय में वृद्धि कर सकें। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और

राजस्थान में भयंकर वर्षा और बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई है। इससे पैदा होने वाली समस्याओं को मुलभूतों के लिए इन राज्यों को अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में 37 करोड़ रुपयों की रकम रखी गई। इस प्रकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में कुल मिला कर 198 करोड़ रुपयों की वृद्धि की जाएगी।

3. 9. यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अगर इतने ज्यादा साधन न जुटाए गए होते तो जिन अतिरिक्त अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने की हमने जिम्मेवारी ली है, उनको देखते हुए यह घाटा काफी ज्यादा होता।

3. 10. कर न देने वालों के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है जिससे कर दाताओं के हृदय में कानून के लिए सम्मान पैदा हो गया है और कर के रूप में अधिक रकम प्राप्त होने लगी। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले वर्षों में अधिकांश आय और सम्पत्ति, कर से बच जाया करती थी। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया कि जो लोग कर देने से बच जाया करते थे उनको अपनी आदतों को सुधारने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। अतः आय और सम्पत्ति को स्वेच्छा-पूर्वक प्रकट करने की एक स्कीम नियत अवधि के लिए घोषित की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत करों की जितनी वसूली हुई वह उससे कहीं ज्यादा हुई जितना कि अनुमान लगाया गया था। करों की वसूली में सुधार होने और अर्थ व्यवस्था के अधिक अच्छी होने के कारण करों की अधिक वसूली होने से राजकोष को भी लाभ हुआ। इन सभी कारणों से बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व में 660 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी जिसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है। लेकिन आय-कर की अधिक वसूली होने के कारण होने वाली आय राज्य सरकारों को भी मिलेगी और करों में उनका अंश लगभग 226 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा।

3. 11. बाजार उधारों से प्राप्त होने वाली आय अब स्वेच्छा पूर्वक प्रकट की गई आय और सम्पत्ति के उस अंश में शामिल की जाती है जो निर्धारित सिक्कुरिटिज़ में लगाई जाती है। अनुमान है कि इन उधारों से बजट अनुमानों की तुलना में 168 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी।

3. 12. अनुमान है कि विदेशी सहायता से बजट अनुमानों की अपेक्षा 554 करोड़ रुपए अधिक की आय होगी। इस रकम में कुदमूख परियोजना और आर्थिक विकास के लिए चालू वर्ष में ईरान से प्राप्त 204 करोड़ रुपयों की सहायता शामिल है।

3. 13. ऊपर जिन अधिक प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है, उनके बावजूद चालू वर्ष में 490 करोड़ रुपयों का बजट घाटा होगा। यहां मैं यह और कहना चाहूंगा कि बजट का 490 करोड़ रुपए का यह घाटा 100 करोड़ रुपए कम हुआ होता अगर हमने भारतीय रिजर्व बैंक से इतना ही विशेष उधार लिया होता जिसकी परिकल्पना मूल बजट में की गई थी।

IV

1976-77 के लिए बजट अनुमान

4. 1. 1976-77 के बजट की सबसे प्रमुख विशेषता पूर्ण निवेश में और अधिक उल्लेखनीय वृद्धि करना है जिससे देश सामाजिक न्याय के साथ द्रुतगति से संवृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके।

1.2. अनुमान है कि करों की मौजूदा दरों के आधार पर 7837 करोड़ रुपयों का सकल कर राजस्व प्राप्त होगा जो 1975-76 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 367 करोड़ रुपए ज्यादा है। 367 करोड़ रुपयों की इस अतिरिक्त आय में से केन्द्र को 346 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। आयोजना की पूंजी में वृद्धि करने तथा उत्पादन को और अधिक बनाए रखने के लिए और अधिक मशीनरी आदि का आयात करने से सीमा शुल्कों से 113 करोड़ रुपए अधिक की प्राप्ति होगी। संघ उत्पाद शुल्कों से चालू वर्ष में 261 करोड़ रुपए अधिक की आय होने की आशा है। चुंकि स्वेच्छापूर्वक आय और सम्पत्ति को प्रकट करने की स्कीम के अधीन अधिकांश राजस्व चालू वर्ष में वसूल हो जाएगा इसलिए आय कर से 103 करोड़ रुपए कम की प्राप्ति होगी।

4.3. बाजार उधारों से चालू वर्ष के 453 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 535 करोड़ रुपयों की आय का अनुमान है। इसमें स्वेच्छापूर्वक आय और सम्पत्ति को प्रकट करने की स्कीम के अधीन लगाई जाने वाली पूंजी शामिल नहीं है। अल्प बचतों से भी अगले वर्ष 40 करोड़ रुपए अधिक की आय होगी।

4.4. विदेशी सहायता से 1341 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है जिसमें नए करारों के अधीन मिलने वाली सहायता या जो सहायता मिल चुकी है, वह भी शामिल है।

4.5. जहां तक व्यय का संबंध है, रक्षा व्यय पर 2544 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं जो 1975-76 के संशोधित अनुमानों से जिनमें 2410 करोड़ रुपयों की व्यवस्था है, कुछ ही ज्यादा हैं। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए चालू वर्ष के 250 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की अपेक्षा 300 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। पहली मार्च 1976 से उर्वरकों की खरीद व बिक्री को एक नया रूप दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम उर्वरक आयात करने का खर्च सरकार को देगा और इन उर्वरकों के वितरण का प्रबंध करेगा। अन्य गैर-आयोजना खर्च को भारी कटौती कर कम से कम किया जा रहा है जिससे कि यथासंभव जो धन बचेगा उसे आयोजना पर लगाया जा सके।

4.6. कीमतों के बढ़ने के कारण पेंशन पाने वालों को हाल के वर्षों में जो दिक्कतें हुई हैं, सरकार उनके प्रति चिन्तित रही है। रहन-सहन के खर्च में वृद्धि होने के कारण उन्हें जो सहायता दी गई थी, वह पिछली बार पहली अप्रैल 1974 से दी गई थी। रहन-सहन के खर्च में बाद में और अधिक वृद्धि होने के कारण तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें पेंशन की दस प्रतिशत रकम की अतिरिक्त तबर्ष सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं जो कम से कम 10 पए और अधिक से अधिक 50 पए होगी। मैं परिवार पेंशन पाने वालों को भी वह राहत जो पहले संजूर की जा चुकी है तथा कुछ अन्य राहत जो अब पेंशन वालों के लिए प्रस्तावित की जा रही है, देने का प्रस्ताव करता हूं। यह सहायता पहली अक्टूबर 1975 से दी जाएगी। इस काम के लिए अगले वर्ष के बजट में 37 करोड़ रुपयों की रकम रखी जा रही है।

4.7. मैं अब 1976-77 के आयोजना परिव्यय पर आता हूं। केन्द्रीय बजट में केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए 4759 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसमें राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं, पहाड़ी क्षेत्रों और जन जाति क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं के लिए व्यवस्था, उत्तर पूर्वी परिषद् की आवश्यकताओं और ग्राम बिजलीकरण निगम के माध्यम से विद्युत् स्कीमों के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए 1412 करोड़ पए शामिल हैं। इसमें राज्यों को विशेष अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में देने के लिए 294 करोड़ पए शामिल हैं जिसके न होने पर राज्यों को सिंचाई और विद्युत् के आधारभूत

क्षेत्रों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी लगाने में धन के अभाव का सामना करना पड़ता। बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए 3347 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 1976-77 में केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल परिव्यय जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक व अन्य साधन शामिल हैं, 4090 करोड़ रुपए रखे गए हैं जब कि 1975-76 में इसके लिए 3154 करोड़ रुपए रखे गए थे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं, 1975-76 के 2812 करोड़ पयों की तुलना में 3762 करोड़ रुपयों की होंगी। कृषि, सिंचाई, विद्युत्, पेट्रोलियम, कोयला, उर्वरक, इस्पात, परिवहन और संचार के क्षेत्र में जो परियोजनाएं इस समय चालू हैं उनको पूरा करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए हमें उनका चुनाव उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रख कर करना होगा।

4.8. केन्द्रीय बजट में कृषि और संबद्ध कार्यक्रमों के लिए 323 करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कार्यक्रमों जैसे सूबाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई क्षेत्र विकास कार्य, ब, छोटे और सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विशेष कार्यक्रम और खेती के लिए काम में आने वाली चीजों की और उनके लिए सामान्य रूप से अधिक से अधिक ऋण दिलाने की स्कीमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केन्द्रीय परिव्यय में 473 करोड़ रुपए तक की पूर्ति राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं से की जाएगी जिसमें से 148 करोड़ रुपए लघु सिंचाई स्कीमों के लिए होंगे। लघु सिंचाई से 1976-77 में 10 लाख हेक्टेयर और भूमि में सिंचाई की जाने लगेगी।

4.9. केन्द्रीय बजट में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 20 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें से 12 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 673 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में आयोजना की अवधि में 50 लाख हेक्टेयर और भूमि में बड़ी व मध्यम सिंचाई की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। इसकी तृप्ति में अगले वर्ष जितनी पूंजी लगाई जाएगी उससे 10 लाख हेक्टेयर और भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

4.10. केन्द्रीय बजट में 129 करोड़ रुपए विद्युत के विकास के लिए रखे गए हैं जिनमें से 74 करोड़ रुपए केन्द्रीय थर्मल और पनबिजली स्कीमों और अन्तर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइनों के लिए और 55 करोड़ रुपए न्यूक्लियर विद्युत् परियोजनाओं के लिए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं में विद्युत् के लिए परिव्यय में भी वृद्धि होगी और इसके लिए 1975-76 में 983 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 1976-77 में 1290 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चालू वर्ष में हमने 1800 मेगावाट विद्युत् पैदा की है। इसकी अपेक्षा अगले वर्ष के लिए 2500 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत् पैदा करने का लक्ष्य रखा जाएगा।

4.11. देश में ऊर्जा के साधनों का विकास करने की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाए थोड़ा है। इसलिए पेट्रोलियम और पेट्रो-केमिकल्स के लिए बजट में धन राशि बढ़ा कर 1975-76 में 170 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 1976-77 में 274 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें से 73 करोड़ रुपए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को देने के लिए रखे गए हैं जिससे समुद्र तट पर तेल की खोज करने के काम में प्रगति को बनाए रखा जा सके और समुद्र तट से दूर तेल की खोज करने के काम में और तेजी लार्दी जा सके। आशा है देश में कच्चे तेल का उत्पादन चालू वर्ष में 82 लाख टन की अपेक्षा 1976-77 में 90 लाख टन हो जाएगा। इस अवधि के अन्त तक समुद्र तट से दूर के

कुप्राँ से तेल प्रतिदिन निकाला जाने लगेगा और इसका वार्षिक उत्पादन 20 लाख टन होने लगेगा। कोरुनोरिकाइनरी के विस्तार, सतायाबोरंगाम-कोएजी पाइप लाइन, सथरा रिकाइनरी और बीरंगाम-सथरा पाइपलाइन के वास्ते भारतीय तेल निगम को देने के लिए 65 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त रकम रखी गई है। भारतीय पेट्रो-केमिकल्स निगम को पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स के लिए जिसमें नव्या कैंकर और डाउनस्ट्रीम यूनिटें शामिल हैं, 81 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1976-77 में पेट्रोलियम क्षेत्र का कुल आयोजना परिव्यय चालु वर्ष के 368 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 485 करोड़ रुपए होगा।

4.12. निश्चय ही यह बड़े सन्तोष की बात है कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण होने के बाद और सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों के परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। 1976-77 में कोयले के लिए बजट में 277 करोड़ रुपए रखे गए हैं जब कि 1975-76 में 229 करोड़ रुपए रखे गए थे। आशा है कि 1976-77 में कोयले का उत्पादन बढ़ कर 1080 लाख टन हो जाएगा जबकि 1975-76 में 980 लाख टन हुआ था।

4.13. खेती में उत्पादन में काम आने वाली चीजों में उर्वरक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बजट में इस क्षेत्र के लिए 1975-76 में 290 करोड़ रुपए रखे गए थे जब कि अगले वर्ष के लिए यह रकम बढ़ा कर 434 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें अटिछा और पानीपत परियोजनाओं के लिए 171 करोड़ रुपए और फ़ून्तुर उर्वरक परियोजना के लिए जो एक सहकारी क्षेत्र है, 13 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त रकम रखी गई है जिससे यह परियोजनाएं निश्चित रूप से अपने प्रयुक्तार पूरी हो सकें। चालू वर्ष में उर्वरकों के सरकारी कारखानों ने अपने उत्पादन में पिछले वर्ष के उत्पादन को तुलना में पोषक तत्वों की दृष्टि से 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। आशा है कि उनका उत्पादन अगले वर्ष में 11 लाख टन से अधिक होगा।

4.14. इराक के क्षेत्र के लिए अगले वर्ष बजट में दुआनी अर्थात् 402 करोड़ रुपए की राशि रखी जा रही है। इसमें से मिनाई कम्प्लेक्स आदि के लिए 119 करोड़ रुपए और बोकारी के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुत्रुब कच्चा लोहा परियोजना के लिए जो पूरी तरह से ईरान से प्राप्त आर्थिक सहायता से कर्मचारी की जा रही है, उसके निर्माण कार्यों और मंगलोर पत्तन में संबद्ध सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह परियोजना पूरी तरह से निर्यात प्रधान है और इससे ईरानी इराक उद्योग को कच्चे लोहे का कंटेनर सप्लाई किया जाएगा।

4.15. परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए 597 करोड़ रुपए रखे जाएंगे जिसमें से 271 करोड़ रुपए रेलवे के लिए हैं जिसकी अपनी आयोजना का परिव्यय 411 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रेलवे को 160 करोड़ रुपयों के उधार के रूप में भी सहायता की आवश्यकता होगी जिससे वह सामान्य राजस्व के प्रति अपनी मौजुदा देदारियों को पूरा कर सकें।

4.16. उद्योग के लिए बजट में जो रकम रखी गई है उसमें हिन्दुस्तान कागज निगम को उसकी चीगांव, कच्चार, नागाज़ैड और केरल परियोजनाओं के लिए 36 करोड़ रुपए और सीमेंट निगम परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन करने के निमित्त परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता और पूंजी निवेश के लिए 10 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं।

4.17. खादी, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए 52 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

4. 18. सामाजिक सेवाओं पर परिरक्ष्य में भी वृद्धि की गई है। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और समेकित शहरी विकास कार्यों के लिए चालू वर्ष की तुलना में अधिक व्यय की गई है। खास तौर से, जन जातियों के लिए उप-आयोजनाओं पर केन्द्र की रकम दुगुनी बढ़ा कर 40 करोड़ रुपये रखी गई है और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर रकम 1975-76 से 20 करोड़ रुपये की अपेक्षा बढ़ा कर 36 करोड़ रुपये रखी गई है।

4. 19. जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, कीमतों में वृद्धि होने से औद्योगिक कामगारों और वेतन पाने वाले कर्मचारियों की हालत बहुत खराब हो गई थी। इन कमजोर वर्गों के लोगों की वास्तविक आय को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 1974-75 में कई उपाय किए गए थे। इनमें से एक उपाय यह था कि महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की जाए उसकी आधी रकम को जमा के लिए रोक रखा जाए। इन उपायों से जो लाभ हुआ है उसका अब सदुपयोग करना जरूरी है। अगले वर्ष के आयोजना परिरक्ष्य में अधिक वृद्धि किए जाने से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और मौजूदा रोजगार भी सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि मुद्रा पूर्ति के विस्तार पर कड़ी नजर रखी जाए जिससे कीमतों को बढ़ाने वाले तत्व उभरने न पाएं। इसी उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया है कि बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का आधा भाग जो जमा के लिए रोक लिया जाता है उसे जुलाई 1976 से अर्थात् जब से संबद्ध मौजूदा कानूनी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और एक वृत्त के लिए रोक रखा जाए। बढ़ाई गई इस अवधि में जमा रकमों का उपयोग आयोजना के लिए किया जाएगा। इस अवधि में जमा रकमों पर पहले की तरह 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा और ब्याज समेत समूची रकम जुलाई 1978 से शुरू करके बराबर-बराबर की पांच किस्तों में अभिदाता की भविष्य निधि में वापस कर दी जाएगी। इस संबंध में आवश्यक विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार ने जमा के लिए अतिरिक्त वेतन और महंगाई भत्ते की रोक रखी गई रकम को मौजूदा स्कीम के अनुसार अवधि पूरी होने पर लौटा देने का जो आश्वासन दिया था उसे वह पूरा करेगी। अतः कर्मचारियों को 1976-77 में 270 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

4. 20. औद्योगिक कामगारों के कल्याण की ओर सरकार का हमेशा विशेष ध्यान रहा है। औद्योगिक कामगारों के लिए समाज सुरक्षा की कई स्कीमें चल रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और अभी हाल ही की परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा स्कीम के व्योरे से माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि समाज सुरक्षा की एक अन्य स्कीम के शुरू करने का फैसला किया गया है जिससे कामगारों को अपनी तरफ से कोई अदायगी किए बिना बीमे की सुरक्षा प्राप्त होगी। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि नौकरी के दौरान किसी कामगार का देहान्त होने की स्थिति में, उसके आश्रितों को उस कामगार के देहान्त से पहले उसकी भविष्य निधि में पड़ी तीन वर्षों की औसत राशि के बराबर अतिरिक्त अदायगी पाने का अधिकार होगा, लेकिन यह अदायगी 10,000 पए से अधिक नहीं होगी। यह स्कीम उन सभी अभिदाताओं पर लागू होगी जिनकी भविष्य निधि में पिछले तीन वर्षों में कम से कम 1,000 रुपये पड़ा रहा हो। अनुमान लगाया गया है कि एक कामगार की औसत राशि लगभग 3500 रुपये होगी। इससे यह पता चलता है कि कामगारों को कितनी राहत उपलब्ध होगी। इस स्कीम के लिए धन की व्यवस्था करने में सरकार नियोजकों के साथ हिस्सा बंटाएगी। मुझे यकीन है कि सदन के सभी वर्ग इस नए कदम का स्वागत करेंगे। सदन में आवश्यक विधेयक श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

4. 21. संभावित खर्च और उपलब्ध साधनों को देखते हुए करों की मौजूदा दरों के आधार पर 1976-77 के केन्द्रीय बजट में 368 करोड़ पए का घाटा रहेगा।

Budget 1976-77

Speech of

Minister of Finance

15th March, 1976

Sir,

1.1. It is my privilege, Sir, once again, to present the Budget to this august House.

1.2. Last year, when I outlined the Budget proposals for 1975-76, the emphasis was on stabilisation and consolidation. The economy was just then recovering from a severe bout of inflation; and the agricultural situation was none too secure.

1.3. The outlook has changed in many ways this year, thanks to resolute and dynamic leadership. The New Economic Programme has generated an unprecedented sense of discipline and dedication in every facet of our economic life. Taking advantage of the improved situation, additional investments in important sectors were authorised during the latter half of 1975-76 and the country is now poised for a major advance in its path towards progress. I am seizing this opportunity to step up the tempo of development further and to impart an added dynamism to the economy. I shall give you the details presently. But Hon'ble Members would, I am sure, be glad to be told straightaway that the Plan outlay of Rs. 7852 crores for 1976-77 represents an increase of 31.6 per cent over the allocation for 1975-76. This marks the highest step up in development outlays in any one year since the beginning of the era of planning in our country.

1.4. The main thrust in this Budget is thus towards accelerated growth. But considerations of stability will continue to be important. The world around us is still subject to considerable buffeting, from price inflation in some areas and from recession in some others. For the first time in post-war history, the volume of world trade registered a significant decline in 1975. This is associated with the fall in the level of economic activity in the OECD countries. There are now signs of recovery in some of the countries, but they appear to be weak. Inflation continues to ravage a number of countries. All this implies a strain on the balance of payments situation for developing countries which are not exporters of petroleum. Our economy, though more strongly placed than some others, is not entirely immune to these pressures. Its sound management will continue to call for the utmost vigilance from all of us.

1.5. India's economic performance during the current year has been a source of satisfaction, indeed pride, to all of us. There has been all-round improvement in production. Key sectors of the economy—in agriculture, in industry, in mining, power, transport and the like—have touched new peaks in performance. The country has had the unique distinction of sustaining a declining trend in prices since October 1974. The wholesale price index for the week ending February 21, 1976 declined to 288, and is about 7.3 per cent lower than a year ago; last year, at this time, prices were 12.5 per cent higher than the earlier year. Consumer prices too have shown a declining trend. The all India Industrial Workers Consumer Price Index was 298 in January 1976 as compared to 326 in January 1975—a decline of 8.6 per cent. I would also like to bring to the notice of Hon'ble Members that the 12-monthly moving average of the consumer price index has come down to 318.6. This success in the struggle against inflation has helped to dispel the mood of pessimism and doubt which prevailed during 1973-74. The manner in which this battle was won, despite heavy odds is living proof of the basic strength and resilience of the Indian economy.

1.6. Last year, I had invited the attention of Hon'ble Members to the need not only of holding the price line, but also of taking positive steps to stimulate growth in the economy. It is therefore a matter of particular satisfaction that the favourable turn in prices during the year has been accompanied by a welcome acceleration in the rate of growth of the economy. On present indications, national income in real terms will increase by about 5.5 per cent in 1975-76. This is attributable to the many determined efforts made by the Government, particularly since the launching in July 1975 of the New Economic Programme, to remove the various obstacles that come in the way of increased production in factories and farms. The prospects for agricultural development have improved greatly on account of the vigorous steps taken to increase the supply of quality seeds, water and fertilisers. The determined action taken to increase the production of such vital inputs as power, coal and steel augurs well for the further growth of industrial production. The country's external payments will also derive considerable benefit from measures adopted against smuggling, and preventing leakage of foreign exchange through unauthorised channels. The fact that at the end of the current year food stocks with public sector agencies will be as high as about 11 million tonnes lends considerable strength to the economy. Altogether, the many beneficial effects of strict enforcement of economic discipline can be easily perceived by any impartial observer of the Indian economic scene. The highly satisfactory performance of the economy during 1975-76 now enables us to take further measures to accelerate the tempo of social and economic development in the coming year.

II

2.1. Adequate investment in key sectors of the economy constitutes a basic condition for a sustained increase in the rate of economic growth. It was in pursuance of this objective that the Annual Plan outlay was stepped up by nearly 25 per cent in 1975-76. Fortunately, the present state both of our food economy and our external reserves is such that we can think in terms of a further major increase in investment outlays in 1976-77, without upsetting the stability of prices. Clearly, public sector investment has to play the leading role in this area. Consequently, it has been my foremost concern in the Budget for 1976-77 to provide for the maximum possible increase in investment consistent with the available organisation capacities for physical performance. The Annual Plan for 1976-77 visualises an outlay of Rs. 7852 crores, which, as I said earlier, represents an increase of 31.6 per cent over the Plan outlay for 1975-76.

2.2. I am confident that the contemplated increase in the Plan outlay can be reconciled with continued stability of prices though this is achievable only on the basis of the strictest possible economic discipline. The struggle against inflation was successful only because the country willingly accepted the needed economic discipline. The fact that prices are currently stable does not warrant the conclusion that enforcement of economic discipline can be relaxed. Price stability has to be sustained through deliberate cooperative efforts on the part of all sections of the community. It would be a grave mistake to take price stability for granted. If we are not vigilant, inflation will raise its ugly head again. This means that the planned increases in investment must, to the maximum extent possible, be financed through a genuine increase in savings. It also means that the community must voluntarily agree to sacrifice current consumption for the sake of accelerated growth in the future. Our economic policies must assist in promoting the growth of investment and savings. Later in my speech, I shall describe the manner in which our tax system is being adapted to facilitate this outcome. At the same time, every effort must be made to curb the growth of non-development expenditure. The general improvement in discipline since the declaration of Emergency has not only led to increased efficiency in Government administration, but also to considerable saving on account of overtime payments. We have to sustain the momentum. In the current year, public sector enterprises have shown encouraging results with the growth rate of production reaching about 15 per cent. We must continuously improve upon this performance so that the country gets the maximum yield from the massive investment outlays of the past. Similarly, the private sector must also accept the inescapable need for the utmost discipline in the use of both real and financial resources. Credit policies must of course respond to changing economic needs. Nevertheless, there can be no getting away from the basic commitment to a rational system of credit use in line with national priorities. The lending pattern of term financing institutions must also be consistent with national

priorities. Effective arrangements for procurement and public distribution of consumption goods must also be an essential component of the national economic scene.

2.3. In my budget speech last year, I had indicated the broad sectoral priorities underlying the budget proposals for 1975-76. These priorities are still valid. It does not require much argument to prove that abolition of mass poverty in a country such as ours can be ensured only through a sustained attack on rural poverty. As Mahatma Gandhi reminded us so often, India lives in its villages. This means, the foremost priority must continue to be given to programmes of agricultural development and such supporting sectors as power, irrigation, fertilisers and pesticides. In this context, I would like to emphasise that an effective attack on rural poverty and under development can only be planned in the framework of an integrated programme of rural development based on detailed knowledge of local needs, resource endowments and potentialities. The focus must be on maximum utilisation of locally available resources, including local manpower, rather than on the introduction of large inputs from outside. We have to evolve operational district plans which fully take into account the precise and separate requirements of each area. For this purpose, a comprehensive survey of natural resources assumes great urgency. We have to make full use of the potential offered by modern science and technology for the regeneration of our rural economy.

2.4. The over-all aim of our approach should be to evolve an operational strategy with the twin objectives of productive employment of the available work-force and of the scientific utilisation of all our natural resources. It is true that such a development strategy cannot be put into operation overnight. Much spade work is necessary before genuinely operational programmes can be devised. There must be scope for innovation and adaptation in the light of varying needs and circumstances. For such efforts in the field of integrated rural development a sum of Rs. 15 crores has been earmarked in the Central Budget for 1976-77. I hope that on the basis of experience gained in 1976-77 we shall be able to expand progressively the scope of this programme.

2.5. There is a very close relationship between modern scientific agriculture and industry. Progress in agriculture depends crucially on the supply of inputs such as quality seeds, water, power and fertilisers. In the current year, the National Seeds Project has made satisfactory progress and there is currently no shortage of quality seeds. The speed with which inter State river disputes have recently been resolved will surely facilitate a faster and more rational development of the country's vast water resources.

2.6. The experience of the last few years shows the grave risks inherent in excessive dependence on imported supplies of fertilisers. We, therefore, need to push ahead as fast as we can with our fertiliser programme. I derive considerable satisfaction from the fact that the utilisation of fertiliser capacity in the country has improved considerably during the current year. Today it can be said with confidence that we have no shortage of fertilisers.

2.7. Government have recently made a review of fertiliser prices, having regard to the importance of ensuring that the output-input ratio in agriculture does serve to stimulate further investment and thus larger production. Hon'ble Members would be happy to learn that it has been decided to reduce the price of urea from Rs. 1850 to Rs. 1750 per tonne. There is also need to promote balanced application of on Nitrogen Phosphorus and Potash. The consumption of phosphatic and potassic fertilisers has lagged behind the desired levels. Government have therefore decided to effect a reduction in the prices of all indigenously produced phosphatic fertilisers and some select categories of imported phosphatic fertilisers by Rs. 1250 per tonne of P_2O_5 . The price of muriate of Potash will also be reduced from Rs. 1085 to Rs. 900 per tonne. I shall also refer later on to proposals in regard to imported rock phosphate. I am confident that these price reductions would serve to step up levels of fertiliser consumption.

2.8. Modern agriculture requires vastly increased inputs of credit. Since nationalisation, commercial banks have expanded greatly their activities in the rural areas. There is, however, still a vast gap between what is available and what is needed. This gap is no sought to be filled partially by the newly established regional rural banks which will lay special emphasis on meeting the credit needs of the more vulnerable sections of rural community.

2.9. One cannot over emphasise the need for expanding the production of such critical inputs as power, coal, oil and iron and steel for the development of the country's economy, particularly its industrial base. Production of these items has shown an encouraging trend in 1975-76. Production of coal is expected to reach the record level of 98 million tonnes in 1975-76. The generation of power will show an improvement of about 13 per cent. Yet, there is still a pressing need to push ahead at a faster pace. The establishment of super thermal power stations constitutes an essential plank of the programmes to rid the country of continuing power shortages. The oil exploration programme has gained considerable momentum both on-shore and off-shore and on present indications the medium-term prospects appear highly favourable. In order to sustain growing production in the years to come, we must provide all these industries with adequate investible resources. This is precisely what is being done in the Budget for 1976-77.

2.10. In planning the national investment strategy, we have also to ensure that the level and the sectoral composition of private investment are in line with our national priorities. I recognise that in recent years, investment levels in some major industries have fallen short of requirements. Government have adopted several measures to improve the profitability of some priority industries. Pricing policy has been made more flexible. In some cases price have been decontrolled while in others a system of dual prices has been adopted with a view to providing a reasonable return to the investors consistent with protecting the users in priority sectors against excessive price increases. It goes without saying that in a fast changing world, our pricing policies must retain the needed degree of flexibility to ensure a proper balance between the interests of producers and of consumers.

2.11. I am aware that in recent years there has been a steep escalation in capital costs which has affected the profitability of new investment. This could not have been foreseen when the decision to withdraw the development rebate was taken some years ago. I am convinced that the problems created by escalation in capital costs are genuine, and means have to be found to tackle them effectively. This Budget will attempt to do this.

2.12. Under the existing Capital Issues (Exemption) Order, the specific consent of the Controller of Capital Issues is required only for bonus issues and for issue of capital by companies registered under the MRTP Act. In the case of other issues, companies have only to file a statement of proposals with the Controller if the issue exceeds Rs. 25 lakhs during a twelve-month period. It is now proposed to raise this limit to Rs. 50 lakhs. There will, however, be no change regarding the regulations covering bonus issues or issues by MRTP concerns.

2.13. It has been a matter of particular concern to us that such important industries as cotton textiles, jute manufactures and sugar have not devoted enough resources to modernisation and expansion. These industries process important agricultural raw materials, and offer direct employment to a large number of workers. They are also a major source of the country's foreign exchange receipts. In addition, cloth and sugar are major articles of mass consumption. The country has, therefore, a vital stake in the good health of these industries. Certain segments of the engineering industries are also faced with 'sickness' which has to be checked in time. In the cement industry, a significant improvement in the economy of production can be secured by a change-over from wet to dry process. The provision of adequate resources for modernisation and rehabilitation of these industries is therefore another matter of high priority. To that end, arrangements are being made to provide the Industrial Development Bank with enough resources to enable it in collaboration with other term-lending institutions, to finance the requirements of modernisation, renovation and rehabilitation of these industries.

2.14. I would like to emphasise that very often lack of effective management is a basic cause of the sickness of an industry. Along with provision of financial assistance, financial institutions should. I feel devise sound mechanisms to tone up the management of assisted concerns. It also needs to be emphasised that sound development of industries such as sugar is also greatly dependent on the adoption of a stable long-term policy for the growth of production of sugar-

cane. Similarly, the progress of the cotton textiles industry is linked to the evolution of a sound policy for the development of raw cotton. Additionally, any integrated textile policy must ensure effective protection for the handloom sector which provides employment to a very large number of poor weavers.

2.15. It is no doubt true that currently some industries are faced with inadequate demand. I would hope that the contemplated increase in Plan outlays for 1976-77 will provide a major stimulus to the greater utilisation of existing industrial capacities. A number of industries producing consumer durables are experiencing considerable difficulties. While there may be a case for the sake of preventing unemployment for helping these industries to tide over transitional problems, their long-term survival is clearly linked to their ability to diversify their activities and to produce the type of goods for which there is likely to be an expanding demand in the country.

2.16. An increase in export volume at an annual rate of over 8 per cent is an essential condition for sustained viability of the country's external payments. Government have recently further simplified procedures and liberalised facilities for exporters. The procedures for payment of cash assistance and duty drawback have been made simpler. Rates of cash assistance have been suitably revised in order to promote the competitiveness of our exports. The country's success in stabilising domestic price levels and the emergence of a buyers' market at home have also enhanced the competitiveness of our exports. The fact that a year in which the volume of world trade declined is likely to witness an increase of 7 to 3 per cent in the volume of our exports is an indication of the growing effectiveness of our export promotion efforts. The modernisation programme for jute, textiles and sugar, I have mentioned earlier, is designed to strengthen further the country's export performance. The recent arrangement to delink the rupee from the pound and determine the rupee's exchange rate by reference to movement in a basket of currencies of India's major trading partners is designed to impart greater stability to the effective exchange rate and to our foreign trade in a world of floating currencies. With its well diversified industrial base, it is possible, as never before, for India to mount a successful export drive.

2.17. Developments in science and technology have convincingly demonstrated that mass poverty is not the inevitable lot of the majority of mankind. The country has an impressive record of achievement in the utilisation of atomic energy, space exploration, and utilisation of modern science for agricultural development. The time has, however, come when the movement for technological change needs a fresh impetus. As part of this process, the Plan allocation for the development of science and technology will be Rs. 156 crores in 1976-77 or an increase of no less than 34 per cent over the likely expenditure of Rs. 116 crores in the current year. Hon'ble Members would no doubt also welcome Government's decision to levy an R&D cess to mobilise resources to finance such ventures. The Ministry of Industry and Civil Supplies would be introducing legislation in this regard in this session.

2.18. Social justice is not merely a matter of increased production even though higher production is an indispensable condition for securing greater social justice. That is why our development strategy has always recognised the need for special programmes catering to the needs of the more vulnerable sections of our society. The 20-point Economic Programme has created a new awareness of the urgency of orderly implementation of such programmes. Effective implementation of measures involving redistribution of surplus land, provision of house sites for the poor and socialisation of vacant urban lands will have a very favourable impact on the structure of income distribution. Progress in this field is proceeding apace. The more vigorous emphasis now being laid on family planning also constitutes an important element of the programme designed to improve the standard of living and the quality of life of the less privileged sections of our society. New initiatives are being planned to step up considerably the speed of construction of low income houses as part of programmes of sound urban development and renewal. However, I would like to emphasise that special programmes of this kind achieve optimum results when they form part of an integrated strategy of development.

2.19. Government recognise that if the process of development is to be speeded up and plans and programmes are to be properly implemented some basic changes are also necessary in the field of financial administration. The existing

system under which accounts are maintained by an agency external to the Ministries and Departments is not conducive to effective financial management. Accounts and Finance should form an integral part of overall management and should play a more meaningful and effective role in selection of projects, allocation of funds, monitoring of expenditure in relation to physical progress, and evaluation of results. In order to integrate accounts with administrative Ministries and Departments, it is proposed to separate accounts and audit and instal a Departmentalised Accounting System. The process of this separation is scheduled to be completed by 21st October, 1976 for all Central Ministries. Under the new scheme, administrative Ministries will take full responsibility for arranging payments, and timely compilation and rendering of accounts. This reform will facilitate the timely receipt of information on the progress of expenditure, and enable a proper analysis of expenditure trends to be effected. There can be little doubt that this flow of information will greatly facilitate the taken of correct decisions, and the adoption of remedial measures wherever called for. Since these changes are fundamental and of a magnitude unprecedented in the annals of Indian administration, care has to be taken to ensure that during the transitional phase, there is no dislocation either in payments or in accounting procedures. Hon'ble Members are doubtless aware that the President has promulgated two Ordinances to achieve these objectives, and to ensure that the necessary expert manpower is available to the Government for discharging the newly acquired responsibilities. In doing so, every care will be taken to see that minimum hardship is caused to the employees, and that the Comptroller and Auditor General is able to discharge his constitutional responsibilities effectively and without disruption. He is fully associated with the reforms and all measures have been taken in close consultation with him.

2.20. Government also attach great importance to the rationalisation and modernisation of procedures relating to the personal claims of Government servants and transactions with members of the public. The existing procedures in regard to pension, gratuity and drawal of salaries of Government officers have been reviewed in depth and a number of steps have been taken to eliminate existing delays in the preparation of pension papers and sanctioning of pension and gratuity. Procedures for payment of salary and allowances of Gazetted Government servants have also been simplified. It is proposed to utilise nationalised banks for financial transactions between Government, its employees and private citizens. The new system will be a considerable improvement over the existing system where such transactions can today be made only at a limited number of treasuries or banks.

2.21. The machinery for tax collection, for checking tax evasion, and for preventing leakage of foreign exchange to illegal channels has been streamlined. The improved collection income tax, despite a reduction in the rates, the outstanding success of the voluntary disclosure scheme, and the sizeable increase in earnings of foreign exchange on invisible account due to effective action against smuggling, are an indication of the success of measures to strengthen the tax collection machinery. I would like to take this opportunity to express my appreciation of the good work done by the staff of the Central Boards of Direct Taxes and of Excise and Customs, of the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Enforcement.

2.22. I would like to point out that prevention of such evils as tax evasion and black money cannot be achieved solely through a tightening of administrative mechanisms. It is equally essential to ensure that our economic policies, including our fiscal policies, minimise the incentives for tax evasion and for generation of black money. As part of this drive, Government have sought to streamline and simplify controls with a view to removing those which have become obsolete or lost relevance, without in any way encouraging greater concentration of economic power. The recent attempts at simplification of procedures and liberalisation of facilities for inward flow of remittances from non-resident Indians abroad are directed to the same objective. Such simplification and liberalisation cannot however be a once and for all process. Some controls will always remain an essential part of our regulatory mechanism for the public good, and have to be accepted as necessary facts of life. Nevertheless, there is clearly a need for continuous efforts to make our control mechanisms, where these are necessary, more effective, to streamline their operations, to identify the broad objectives behind each control instrument and to see if those objectives are really being served or whether an alternative arrangement would not be superior.

23. I believe I have said enough to give Hon'ble Members an idea of the underlying objectives and policies of the Budget for 1976-77. It is now time for me to describe briefly the Revised Estimates for 1975-76 and the main features of the Budget Estimates for 1976-77.

III

REVISED ESTIMATES FOR 1975-76

3.1. The original Budget for 1975-76 envisaged a deficit of Rs. 247 crores. However, due to certain unavoidable increases in expenditure, the current year is now expected to end with a deficit of a higher order. A large part of the additional expenditure involved represents deliberate action on the part of Government designed to accelerate the pace of economic growth.

3.2. Because of recessionary conditions prevailing in international markets, it became necessary to intensify export promotion measures. As a result, expenditure of Rs. 88 crores by Rs. 71 crores,

3.3. Public sector undertakings have greatly improved their working, but some of them, particularly the National Textile Corporation, could not generate enough funds to meet all their obligations. As a result, non-Plan budgetary support for these public sector units had to be increased by Rs. 210 crores over the Budget provision of Rs. 170 crores.

3.4. Taking advantage of the increased production of foodgrains, Government have decided to build up an adequate level of buffer stocks. Budgetary support of the order of Rs. 130 crores had to be provided to the Food Corporation of India for this purpose—Rs. 100 crores as equity capital and Rs. 30 crores as loan. The House will agree that this is a worthwhile investment.

3.5. The original Budget provided for a net outgo of Rs. 140 crores on account of fertiliser transactions. However, as Hon'ble Members are aware, the pool prices of fertilisers were reduced in July, 1975 and again in December, 1975 in order to boost consumption. For this reason, as also the slow initial off-take and consequent lag in recoveries, the net outgo on this account is now expected to increase by Rs. 173 crores.

3.6. Defence expenditure will be higher by Rs. 136 crores due mainly to grant of additional dearness allowance and an upward revision of ration and other allowances. The additional instalments of dearness allowance sanctioned in September, 1975, for which no provision was made at the Budget stage, have cost an extra burden of a considerable magnitude which is reflected in the Revised Estimates under other heads also.

3.7. In spite of the burden cast on the Budget by these commitments, we did not allow our developmental efforts to suffer. Investments in the crucial sectors of the Plan, especially steel, shipping and transport, as also mines, fertilisers, coal and power, were stepped up beyond the level provided in the Budget for 1975-76. The outlay on health and family planning has also become significantly higher. Additional funds have been provided to the Railways to enable them to meet the shortfall in their resources for the Plan which has been stepped up. In this context, I should like to make special mention of the extra provision of Rs. 53 crores for purchase of rolling stock by the Railways, which was also a means of providing stimulus to the engineering industry. In sum, the budgetary provision for various sectors of the Central Plan will be about Rs. 270 crores more than was provided for in the original Budget.

3.8. Budgetary support for the Plans of States and Union territories was originally fixed at Rs. 1054 crores which included a sum of Rs. 100 crores for special assistance to certain States with gaps in their resources to ensure adequate investment in important projects in the core sectors of irrigation and power. A subsequent assessment of the States' resources revealed that these gaps would be of a higher order than earlier envisaged. As a result, provision for special assistance had to be raised to Rs. 175 crores. Following the announcement of the New Economic Programme, additional Central assistance of Rs. 855 crores was allocated to the States to enable them to step up the outlays on selected irrigation and power projects. Certain States like Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan have suffered on account of heavy rains and floods. A sum of Rs. 37 crores has

had to be provided as advance plan assistance to enable them to cope with the resulting problems. In all, the Central assistance to States and Union territories Plans will go up by Rs. 198 crores.

3.9. At this stage it is necessary to state that the budgetary deficit, taking into account all the inescapable additional commitments, would have been much higher but for a significant increase in resource mobilisation.

3.10. As a result of stringent action taken against tax evasion, an atmosphere has been created whereby tax-payers have a greater respect for the law, and tax compliance has improved. The fact must be faced that in the past a considerable part of income and wealth had escaped taxation. After careful consideration, Government decided to provide those who had indulged in tax evasion a last chance to mend their ways. Accordingly, a scheme of voluntary disclosure of income and wealth was announced for a limited period. Disclosures and consequently tax collections, under this scheme have surpassed our original expectations. The Exchequer has also benefited by way of larger collection of taxes as a result both of improved tax collections and greater buoyancy of the economy. All these factors will result in an improvement of Rs. 460 crores in tax revenues as compared to the Budget Estimates inclusive of the States' share. The benefit due to the larger collection of income tax will, however, accrue mainly to the State Governments, and their share of taxes will go up by nearly Rs. 226 crores.

3.11. The receipts from market loans, which now include investment of a part of the voluntarily disclosed income and wealth in specified securities, will be higher than Budget Estimates by Rs. 168 crores.

3.12. Receipts from external assistance are expected to exceed the Budget Estimates by Rs. 554 crores; this figure includes Rs. 204 crores of assistance received during the current year from Iran for the Kudremukh Project and for economic development.

3.13. In spite of improvements in receipts mentioned above, the current year is expected to end with a budgetary deficit of Rs. 490 crores. I should however add that the budgetary deficit of Rs. 490 crores could have been Rs. 100 crores lower had we taken advantage of the special borrowing to that extent from the Reserve Bank of India envisaged in the original Budget.

IV

BUDGET ESTIMATES FOR 1976-77

4.1. The most important feature of the Budget for 1976-77 is a further significant step up in investment so that the country may move forward rapidly towards the realisation of the objective of accelerated growth with social justice.

4.2. Gross tax revenues at the existing rates of taxation are expected to amount to Rs. 7837 crores, showing an increase of Rs. 367 crores as compared to the Revised Estimates for 1975-76. Of the additional accruals of Rs. 367 crores, the share of the Centre would be Rs. 346 crores. Receipts from Customs are likely to go up by Rs. 113 crores as imports next year are expected to be larger in view of the step up in Plan investments, and the need for larger maintenance imports to sustain higher production levels. Union Excise duties are expected to yield Rs. 261 crores more than in the current year. Income tax receipts will be less by Rs. 103 crores, mainly because the bulk of the receipts under the voluntary disclosure scheme will have been realised in the current year.

4.3. Market loans are expected to yield Rs. 535 crores as compared to Rs. 463 crores in the current year. This excludes investments under the voluntary disclosure scheme. Small savings collection are also expected to yield Rs. 40 crores more in the next year.

4.4. Receipts from external assistance are estimated at Rs. 1341 crores which include assistance both in the pipeline and disbursement against new commitments.

4.5. On the expenditure side, the provision for Defence expenditure is Rs. 2544 crores against Rs. 2410 crores in Revised Estimates for 1973-76, which is a small increase. The provision for food subsidy will be Rs. 300 crores as against Rs. 250

crores in the current year. From 1st March 1976, fertiliser transactions have been put on a different footing. The Food Corporation of India will pay the Government for the imported fertiliser and arrange for its distribution. Other non-Plan expenditures are being restricted to the minimum so as to make available the maximum possible resources for the Plan.

4.6. Government have been concerned about the difficulties being faced by pensioners in recent years in the wake of inflation. The last instalment of relief to them on account of the increase in the cost of living was with effect from 1st April, 1974. Considering the subsequent increase in the cost of living, and keeping in view the resources available, I propose to allow them an additional *ad hoc* relief to the extent of 10 per cent of pension, subject to a minimum of Rs. 10 and a maximum of Rs. 50. I also propose to extend to family pensioners the relief earlier granted, as well as the further relief now proposed to be granted, to pensioners. These benefits will take effect from 1st October, 1975. A provision of Rs. 37 crores is being made in the next year's Budget for this purpose.

4.7. I now turn to the Plan outlay for 1976-77. The allocations from the Central Budget for the Central, State and Union territories Plans will be Rs. 4759 crores. This includes Rs. 1412 crores for Central assistance for State Plan and provisions for Union territories Plan, the sub-Plan of the Hills and Tribal Areas, the requirements of North Eastern Council, and assistance for power schemes channelled through the Rural Electrification Corporation. The allocations also include Rs. 294 crores of special advance Plan assistance without which some States would be without adequate resources for the required level of investment in important projects in the core sectors of irrigation and power. The budgetary provision for the Central Plan will be Rs. 3347 crores. The total Central Plan outlay in 1976-77, including internal and other resources of public sector undertakings, will be Rs. 4090 crores, as against Rs. 3154 crores in 1975-76. The State and Union territories Plans will be of the order of Rs. 3762 crores, as compared to Rs. 2812 crores in 1975-76. The greatest stress has been laid on the completion of on-going projects in agriculture, irrigation, power, petroleum, coal, fertilisers, steel, transport and communications. We have had to be rather selective in proposing new starts, having regard to resources in sight.

4.8. The Central Budget provides Rs. 323 crores for agriculture and allied programmes. Special emphasis is being laid on production programmes with an area approach such as the Drought Prone Areas Programme, the Command Area Development Programme, special programmes for small and marginal farmers, and agricultural labour and schemes to increase generally the availability of inputs and credit for agriculture. The Central outlays will be supplemented by outlays in the State and Union territories Plan to the extent of Rs. 473 crores, of which about Rs. 148 crores will be for minor irrigation schemes. The area covered by minor irrigation is expected to increase by one million hectares in 1976-77.

4.9. Provision in the Central Budget for irrigation and flood control will be Rs. 20 crores including an outlay of Rs. 12 crores for flood control schemes. The State and Union territories Plans will provide Rs. 673 crores for major and medium irrigation and flood control. As Hon'ble Members are aware, in pursuance of the 20-point Programme, we have proposed to bring an additional five million hectares under major and medium irrigation during the Plan period. As against this target, the investment proposed next year will create additional potential of the order of one million hectares.

4.10. A sum of Rs. 129 crores has been provided in the Central Budget for power development, including Rs. 74 crores for Central thermal and hydel power schemes, and inter-State transmission lines, and Rs. 55 crores for nuclear power projects. There will also be a significant step up in the outlay on power in State and Union territories Plans from Rs. 983 crores in 1975-76 to Rs. 1290 crores in 1976-77. The target for additional power generation capacity next year will be of the order of 2500 MW, as against the achievement of about 1800 MW in the current year.

4.11. The need for developing indigenous sources of energy cannot be over-emphasised. Accordingly, the budgetary support for petroleum and petro-chemicals has been stepped up from Rs. 170 crores in 1975-76 to Rs. 274 crores in 1976-77, of which Rs. 73 crores will go to the Oil and Natural Gas Commission to maintain the tempo of on-shore exploration and for stepping up the pace of off-shore exploration. Indigenous production of crude oil is expected to increase to at least

9 million tonnes in 1976-77 as against 8.2 million tonnes in the current year. The production from off-shore sources by the end of this period will be at a daily rate amounting to 2 million tonnes annually. An additional Rs. 65 crores is being provided to the Indian Oil Corporation for the Koyali Refinery expansion the Salaya Viramgam Koyali Pipeline, the Mathura Refinery and the Viramgam-Mathura pipeline. The Indian Petro-Chemicals Corporation will be provided Rs. 81 crores for the petro-chemical complex comprising the Naphtha Cracker and downstream units. The total Plan outlay in the petroleum sector will be Rs. 483 crores in 1976-77 as compared with Rs. 368 crores in the current year.

4.12. It is indeed a matter of great satisfaction that after the nationalisation of the coal industry and as a result of the concerted steps taken by Government, production of coal has increased rapidly. Budgetary allocation for coal in 1976-77 will be Rs. 277 crores as against Rs. 229 crores in 1975-76. It is expected that the production of coal will go up from 98 million tonnes in 1975-76 to 108 million tonnes in 1976-77.

4.13. Fertilisers being a critical input for agricultural production budgetary provision for this sector is being stepped up from Rs. 290 crores in 1975-76 to Rs. 434 crores in the next year. This includes Rs. 171 crores for the Bhatinda and Panipat projects and Rs. 13 crores for the Phulpur fertiliser project which is in the cooperative sector. Adequate provision has been made to enable on-going projects to be completed according to schedule. In the current year the public sector fertiliser units have improved their production in nutrient terms by about 50 per cent as compared to last year and their production next year may well exceed 1.1 million tonnes.

4.14. The budgetary allocation for the steel sector is being doubled to Rs. 402 crores in the next year. Of this, Rs. 119 crores will be for the Bhilai Complex etc. and Rs. 150 crores for Bokaro. The Kudremukh Iron Ore Project, which is being financed wholly with Iranian assistance, has been provided Rs. 100 crores for project construction and the related facilities required in the Mangalore Port. This is a wholly export-oriented project for supplying iron ore concentrate for the Iranian steel industry.

4.15. The allocation for the transport and communications sector will be Rs. 597 crores, of which Rs. 271 crores will be for Railways which have their own Plan of Rs. 411 crores. The Railways will also need loan support of Rs. 160 crores to enable them to meet their current obligations to the General Revenues.

4.16. The budgetary allocation for industry includes Rs. 36 crores for the Hindustan Paper Corporation for its Nowgong, Cachar, Nagaland and Kerala projects, and Rs. 20 crores for Cement Corporation projects. Rs. 10 crores are being provided for investment and transport subsidy for promotion of industries in backward areas.

4.17. The allocation for Khadi, for village industries, and for small scale industries is Rs. 52 crores.

4.18. Outlays on social services also have been increased. Provisions for education, scientific research, health, family planning and integrated urban development are all higher than in the current year. In particular, the Central allocation for tribal sub-Plans has been doubled to Rs. 40 crores, and that for Hill Areas development has been stepped up to Rs. 36 crores from Rs. 20 crores in 1975-76.

4.19. As Hon'ble Members are aware, industrial workers and salaried employees were the worst hit by rise in prices. It was with a view to protect the real incomes of these vulnerable groups that several anti-inflationary measures were implemented in 1974-75. One of these measures was the impounding of half of dearness allowance increases. It is now necessary to consolidate the gains we have secured. The large step up in the next year's Plan outlay would generate new employment opportunities, and also safeguard existing jobs. At the same time, this calls for a careful vigil on money supply expansion so that inflationary forces are kept at bay. In view of this, Government have decided that impounding of half of dearness allowance increases will continue for one year beyond July, 1976 when the present statutory provisions in this regard expire. Deposits made during the extended period will be used for the Plan. The amounts deposited will earn interest at the same rate as before i.e., 12.5 per cent and will be repaid in five equal annual instalments, inclusive of interest, into the provident fund of the subscribers commencing from

Ju 8. Necessary legislation for this will be introduced in this session. Government will, however, abide by its assurance and repay the instalments of the additional wages and dearness allowances already impounded and falling due in accordance with the existing scheme. The employees will, therefore, have larger disposable incomes to the tune of Rs. 270 crores during 1976-77.

4.20. The welfare of industrial workers has always been of special concern to the Government. A number of social security schemes for industrial workers are in operation. Hon'ble Members are already familiar with the details of the E.S.I. Scheme, the E.P.F. Scheme and the more recent family Pension-cum-Life Assurance Scheme. I am happy to announce that has been decided to introduce yet another social security scheme which will provide insurance to workers without any payment on their part. The salient features of this scheme are that in the event of the demise of a worker while in service, his dependents would be entitled to an additional payment equivalent to the average balance in the provident fund of the worker during the preceding three years subject to a maximum of Rs. 10,000. This scheme would apply to all subscribers who have maintained a minimum balance of Rs. 1,000 during the preceding three years. It has been estimated that the average balance of a worker would be around Rs. 3,500. This would be indicative of the level of relief that will be available. The burden of financing this scheme will be shared by Government with employers. I am sure all sections of this House would welcome this new measure. Necessary legislation will be introduced by the Labour Ministry.

4.21. Taking into account the likely magnitude of expenditure and resources in sight, the Central Budget for 1976-77 shows a deficit of Rs. 388 crores at existing levels of taxation.

बजट 1976-77

भाग "ख"

प्रत्यक्ष कर

1.1. मैं अब प्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों को शुरू करता हूँ।

1.2. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि व्यक्तिगत आय पर आय कर की दरें प्रत्यक्ष कर जरां समिति की सिफारिशों के आधार पर 1974 में घटाई गई थीं। वर्ष 1974-75 का बजट पेश कचते समय मेरे से पहले के सम्मानित वित्त मंत्री ने यह आशा व्यक्त की थी कि इन दरों को घटाने से लोग अधिक संख्या में कर देने लगेंगे। यह आशा पूरी हुई जिसका पता इस बात से लगता है कि पिछले दो वर्षों में आय कर के संग्रह में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि इस वृद्धि के कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे करों की चोरी करने वालों और अन्य आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, फिर भी यह स्पष्ट है कि करों के संग्रह में वृद्धि करने में इन दरों को कम करने का एक बड़ा भारी हाथ रहा। स्वेच्छा से आय व सम्पत्ति को प्रकट करने की म्कीम के अधीन जिस से कर की अधिकतम दर 60 प्रतिशत थी, लोगों ने भारी मात्रा में आय कर दिया। इससे इस बात की पर्याप्त पुष्टि होती है कि अगर कर की दरें संगत हों तो भारत के अधिकांश आय कर दाता कानून का पालन करना और कर देते रहना चाहेंगे। इसलिए मैं व्यक्तिगत आय और धन पर कर की दरों को कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। अधिभार सहित आय कर की अधिकतम सीमान्त दर 77 प्रतिशत से घटा कर 66 प्रतिशत कर दी जाएगी और यह 1,00,000 रुपए से ऊपर की आय सीमा पर व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों पर लागू होगी। इसमें ऐसे परिवार शामिल नहीं हैं जिन में परिवार के एक या अधिक सदस्यों की अकेले की आय छूट की सीमा से ज्यादा है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा करने से राजस्व में कोई कमी आ जाएगी क्योंकि करों की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए इस

समय जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि में यही तर्क निहित कि इससे आयकर दाताओं को भली प्रकार से कर देते रहने की प्रेरणा मिलेगी।

1.3. आयोजना के लिए धन जुटाने के लिए और आयकर दाताओं द्वारा अपनी आय का अधिकांश भाग खर्च करने से कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे कम करने के लिए मैं आयकर दाताओं के लिए अनिवार्य जमा स्कीम को अभी एक और साल के लिए चालू रखने का प्रस्ताव करता हूँ। 25,000 रुपये तक की मौजूदा आय पर अनिवार्य जमा की वर्तमान 4 प्रतिशत की दर जहाँ यथावत् बनी रहेगी वहाँ 25,001 से 70,000 रुपये की आय खंड पर यह दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी। इसी प्रकार 70,000 रुपये से अधिक आय खंड पर यह दर 8 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी जाएगी। इस उपाय से 1976-77 में 80 करोड़ रुपये तक की रकम प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि ईमानदार करदाताओं को, जिन्हें कुछ ऐसी रियायतें मिली हैं जो उन्हें वस्तुतः काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थीं, राष्ट्रीय वचनों में इतना अंशदान करने में आपत्ति नहीं होगी।

1.4. यह सर्वविदित है कि धन कर की मौजूदा ऊँची दरों के कारण अपने धन का कम मूल्यांकन कराने और करों की भारी चोरी करने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। धन कर के संबंध में व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों पर इसकी नई दर शुरू के 5,00,000 रुपये तक के निवल खंड पर अब $\frac{1}{2}$ प्रतिशत, 5,00,001 से 10,00,000 रुपये के खंड पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत, 10,00,001 से 15,00,000 रुपये के खंड पर 2 प्रतिशत और 15,00,000 रुपये से ऊपर के खंड पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगी। इन अविभाजित हिन्दू परिवारों में ऐसे परिवार शामिल नहीं हैं जिनमें परिवार के एक या अधिक सदस्यों की अकेले की सम्पत्ति 1,00,000 रुपये से ज्यादा है। इसके साथ ही मैं सभी हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में धन कर की छूट की सीमा को 2,00,000 रुपये से घटाकर 1,00,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। शहर में खाली पड़ी जमीन पर सीमा के लग जाने और शहरी सम्पत्ति के संबंध में अन्य उपायों को देखते हुए इस समय शहरी जमीन और इमारतों पर जो प्रतिरिक्त धन कर लगता है उसका अब कोई औचित्य नहीं रहा है। इसे अब समाप्त कर देने का प्रस्ताव है।

1.5. मौजूदा दरों पर आय कर और धन कर का संयुक्त आपात कुछ स्तरों पर आय कर के 100 प्रतिशत से ज्यादा बैठता है। करों के मौजूदा ढाँचे को यथार्थपरक नहीं पाया गया है। आय और धन में पाई जाने वाली विसंगति, दरों के इतने ऊँचे होने से कोई ज्यादा कम नहीं हुई है। बल्कि दूसरी ओर इन दरों से करों की चोरी, काले धन का निर्माण और दृश्य परिसम्पत्तियों का अदृश्य परिसम्पत्तियों में परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ है। अर्थ व्यवस्था की इन विकृतियों को दूर करना जरूरी है। कुछ समय के लिए धन कर की दरों में कमी करने से राजस्व में कोई हानि नहीं होती चाहिए। कर के ढाँचे में इस प्रकार का परिवर्तन प्रयोग के आधार पर है। मुझे विश्वास है कि करदाताओं द्वारा करों का अधिक पालन करने और प्रशासन की कुशलता से हम अधिक धन जुटा सकेंगे।

1.6. जो लोग अपने घरों में स्वयं रह रहे हैं और जिन्हें प्रति वर्ष धन की निवल आय के विवरण में अपने इस धन की उचित बाजार कीमत दिखानी पड़ती है उनकी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि ऐसे धन के मूल्य को उस वर्ष के उसके मूल्य पर जिस वर्ष उस धन का निर्माण किया गया या उस वर्ष के उसके मूल्य पर जिस वर्ष संबंधित करदाता ने उसे प्राप्त किया था या 1971-72 के मूल्य पर इनमें से जो भी बाद का मूल्य हो उस पर स्थिर कर दिया जाए।

1.7. माननीय सदस्य जानते हैं कि कर से बचने के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार का अक्सर बहाना किया जाता है। मैंने इसलिए ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवारों की जिनमें परिवार के कम से कम एक सदस्य की अलग से आय छूट की सीमा से ज्यादा है, कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय इस समय मिलने वाली कुछ रियायतों को वापस लेने का प्रस्ताव किया है।

1.8. लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों और अभिनेताओं को अपने अपने व्यवसाय की अवधि में लगातार एक जैसी आय नहीं होती। इस लिए जिन वर्षों में इन लोगों को अधिक आय होती है उन वर्षों में इनकी कर देयता में वृद्धि करने के लिए इन वर्गों के लिए जीवन बीमा, संचयी सांख्यिक जमा, सरकारी भविष्य निधि आदि के माध्यम से जमा की गई जिस राशि को कर से छूट मिलती है उसकी सीमा को 25,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

1.9. मैं अब कंपनी क्षेत्र पर आता हूँ। मैं पूँजी लागत में एकदम से होने वाली वृद्धि के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इससे न केवल क्षमताओं में तेजी से वृद्धि होनी रुक गई है बल्कि इससे मौजूदा ऐसे उपक्रमों पर भी दबाव पड़ा है, जिनको अपनी ऐसी मशीनरी जो घिस चुकी है तथा पुरानी पड़ चुकी है, बदलनी होती है। जब तक कंपनी क्षेत्र को पुरानी मशीनरी की जगह नई मशीनरी लगाने व अपनी मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने में समर्थ नहीं होगा तब तक रोजगार और उद्योगों की संवृद्धि भी खटाई में पड़ जाएगी। अतः राज-कोषीय नीति को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिस से कंपनी क्षेत्र की संवृद्धि और उसको आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके। इसलिए मैंने कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए पूँजी निवेश छूट देने की स्कीम शुरू करने का निर्णय किया है। आरंभिक मूल्यह्रास छूट की मौजूदा स्कीम की जगह पर पूँजी निवेश छूट की प्रणाली शुरू की जाएगी। जिन उद्योगों को इस समय आरंभिक मूल्यह्रास की छूट मिलती है उन्हें 31 मार्च 1976 के बाद नई मशीनरी प्राप्त करने और संयंत्र स्थापित करने पर लागत के 25 प्रतिशत की दर पर पूँजी निवेश छूट दी जाएगी। मैं इन उद्योगों में आठ अन्य प्राथमिकता वाले या निर्यात प्रधान उद्योगों अर्थात् कारबन और ग्रेफाइट उत्पादों, इनआरगेनिक हेवी केमिकल्स, आरगेनिक हेवी केमिकल्स, सिन्थेटिक रबर और रबर केमिकल्स जिनमें कारबन ब्लैक शामिल है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, बुनियादी औषधों, औद्योगिक सिलाई मशीनों और पूरी तरह से तैयार चमड़े और चमड़े की वस्तुओं के जिनमें पूरी तरह या आंशिक तौर पर चमड़े के बने जूते आते हैं, उद्योग को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं सदन का ध्यान इस समय प्रस्तावित पूँजी निवेश छूट और पहले मिलने वाली विकास छूट के बुनियादी अन्तर की ओर दिलाना चाहता हूँ। अगर पूँजी निवेश छूट का इस्तेमाल अगले दस वर्षों के अन्दर नई मशीनरी या संयंत्र प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता तो इसे वापस ले लिया जाएगा और इस पर कर लगाया जाएगा। इस रकम में से कोई भी भ्राम लाभ के रूप में वितरित किए जाने के लिए नहीं उपलब्ध होगा। पूँजी निवेश छूट की मौजूदा स्कीम से प्राथमिकता वाले उद्योगों में पूँजी लगाने में सहायता मिलेगी और कंपनी क्षेत्र को सांख्यिक वित्तीय संस्थाओं पर कम से कम निर्भर रहना पड़ेगा।

1.10. जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है बंगला देश के संकट के समय कंपनियों पर 1971 में 2½ प्रतिशत का आय कर अधिभार लगाया गया था। 1972 में यह अधिभार बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया। जो कंपनियाँ भारत के औद्योगिक विकास बैंक में इतना ही धन पाँच वर्षों के लिए जमा रखेंगी उन्हें इस अधिभार से मुक्त रखा जाएगा। इस उपाय से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि धन एक जगह जमा नहीं होगा और कंपनी क्षेत्र

को पूंजी रूप में उपलब्ध रहेगा। कंपनियों को जो दीर्घ अवधि पूंजी लाभ होते हैं उनके सों में पूंजी लाभ कर को दरों को भी कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

1.11. व्याज की दरों में वृद्धि होने के कारण सुरक्षित पूंजी निवेश से अब काफी लाभ होने लगा है। कंपनियों के शेयरों में जोखिम वाले पूंजी निवेश को और लाभकारी करने के उद्देश्य से मैं कंपनी (लाभ) अधिभार अधिनियम, 1964 के अधीन लाभ की जितनी रकम पर शुल्क लगता है उसे निविष्ट पूंजी के 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह नई सीमा, कंपनी को अपनी पूंजी के आधार पर निश्चित की जाएगी और इस रकम में दीर्घ अवधि के उधार और ऋण पत्र शामिल नहीं होंगे।

1.12. यह बात बार-बार कही जाती रही है कि व्याज की मौजूदा ऊँची दरों का पूंजी निवेश और उत्पादन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। करों ही दरों का मौजूदा स्वरूप हमारी ऋण नीति का आवश्यक अंग है जिससे कीमतों को बढ़ाने वाले तत्वों को नियंत्रण में रखने में सहायता मिलती है। फिर भी औद्योगिक परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैं पूंजी संयंत्रों और मशीनरी की खरीद के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों को दिए गए दीर्घ अवधि के आधार पर इन बैंकों को मिलने वाले व्याज को व्याज कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जो व्याज कर अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत लगाया जाता है। इस सदन को स्मरण होगा कि व्याज पर कर मूलतः नियामक उपाय के रूप में लगाया गया था।

1.13. विदेशी कंपनियों पर कर की मौजूदा प्रणाली में प्रशासनिक कठिनाइयाँ आती हैं और राजस्व की अनिश्चितता बनी रहती है इस प्रणाली को सरल बनाने के उपाय के रूप में मैं, इन विदेशी कंपनियों को 31 मार्च, 1976 के बाद किए गए अनुमोदित करारों के अधीन भारतीय कंपनियों से प्राप्त होने वाली सकल रायल्टियों की रकम पर 40 प्रतिशत की समान दर से आय कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। अनुमोदित करारों के अधीन भारत के बाहर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की कंपनियों को एकमुश्क अदायगियों के तौर पर प्राप्त सकल राशि पर 20 प्रतिशत की समान दर से कर लिया जाएगा। मौजूदा करारों के अन्तर्गत विदेशी कंपनियों को जो रायल्टी और तकनीकी सेवा-फीस मिलती है उस पर कर वर्तमान दर से लिया जाता रहेगा पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यह होगा कि इस तरह की आय प्राप्त करने के लिए इन कंपनियों को अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली सकल रकमों के 20 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

1.14. विदेशी कंपनियों को मिलने वाले लाभांश की सकल राशि पर 25 प्रतिशत की समान दर से कर लिया जाएगा। इसके अलावा, भारत में होने वाले लाभों में से घटाए जा सकने वाले मुख्य कार्यालय के खर्च की सीमा निर्धारित की जाएगी। इस तरह के खर्च की कटौती भारत में होने वाले मुनाफे के लगभग 5 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी।

1.15. भारतीय जीवन बीमा निगम पर कर लगाने की प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार बीमांककीय मूल्यांकन करने पर निकलने वाले अधिशेष के वार्षिक औसत को बीमा कारबार का करयोग्य लाभ माना जाएगा। इस प्रकार के लाभों पर 12½ प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा।

1.16. मकानों की खास कर ऐसे मकानों की जिनकी समाज के अपेक्षाकृत निचले वर्ग के लोगों को जरूरत है, भारी कमी है। मकानों के निर्माण कार्य को एक बड़े उद्योग

का दर्जा दिया जाना उचित ही है। मानव की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता रहने के लिए मकान की होती है। अतः इससे न केवल यह आवश्यकता पूरी होती है बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इस उपेक्षित किन्तु एक आवश्यक क्षेत्र के लिए मैं पहली अप्रैल 1976 से नए बने मकानों को जिनकी कुर्सी का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, पांच साल के लिए धन कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब मालिकों द्वारा अपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों, के लिए बनाए गए उन मकानों के सम्बन्ध में 20 प्रतिशत की प्रारम्भिक मूल्यह्रास छूट मिलेगी, जो 10,000 रुपये तक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिहायशी इस्तेमाल के लिए हों; आजकल यह छूट 7500 रुपये तक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिहायशी इस्तेमाल के लिए बनाए गए मकानों के संबंध में मिलती है।

1.17. विदेशी मुद्रा साधनों को बढ़ाने के उपाय के तौर पर मैं अनुमोदित करारों के अधीन लिए गए उधारों पर औद्योगिक उपक्रमों द्वारा देय ब्याज की रकम को आय कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों तथा निर्यात प्रधान उद्योगों के इक्विटी शेयर में गैर-आवासी भारतीयों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी को भी धन कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। विदेशों से वापस लौटने वाले जो भारतीय विदेशों में की गई अपनी बचतों को भारत में लाएंगे उन्हें इन बचतों के संबंध में सात वर्षों तक कोई भी धन कर नहीं देना होगा।

1.18. हमारा अनुमान है कि प्रत्यक्ष करों में विभिन्न प्रकार की रियायतें देने से राजस्व में जो कमी होगी उसे कर के अधिक पालन से तथा प्रशासन में सुधार लाकर पूरा किया जाएगा।

II

अप्रत्यक्ष कर

2.1. अब मैं अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों को लूंगा।

2.2. इस वर्ष का बजट तैयार करने से पहले मुझे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योग तथा वाणिज्य के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कई मूल्यवान सुझाव दिए जिनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने इन सुझावों पर सावधानी से विचार किया है। वर्ष के दौरान मैंने उत्पादन शुल्क के ढांचे की व्यापक रूप से जांच करवाई और इस जांच के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में सुधार लाने की जरूरत महसूस हुई है। खासकर ऐसे कर लगाने की प्रणाली अपनाने की संभावना का अध्ययन किया गया है जिसमें मूल्य को भी शामिल किया जा सके। चूंकि इस अध्ययन में जिन समस्याओं का पता लगा है वे बहुत ही जटिल हैं और उनके प्रभाव भी दूरगामी होंगे इसलिए अप्रत्यक्ष करों के मौजूदा ढांचे की जांच करने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से मैं एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

2.3. अब मैं मात्रानुसार उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्तावों को शुरू करता हूँ। इस समय सूती कपड़ों पर मात्रानुसार कर लगता है और उनका कर-भार कपड़े की कीमत पर नहीं निर्भर करता। हालांकि मौजूदा दरें काफी पेचीदा हैं और यह औसत काउण्टों के आधार पर तथा सूती कपड़ों पर जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उन दोनों के आधार पर लगाई जाती है और इस प्रकार उत्पाद शुल्कों के बोझ का वितरण समान नहीं होता। इसके अतिरिक्त जहां उद्योग में नाना प्रकार का अन्तर हो वहां इन

टैरिफों को लगाने में भी काफी कठिनाइयाँ होती रही हैं। इसलिए इस प्रणाली में बहुत पहले ही सुधार कर देना चाहिए था। मैंने अब निर्णय किया है कि सूती कपड़ों पर मात्रानुसार कर के बदले मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। इससे समाज के अपेक्षाकृत अधिक कमजोर वर्गों के लोगों को राहत मिलेगी जो कम कीमत के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जिन में अच्छी किस्मों के कपड़े के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमतों की अदायगी करने का सामर्थ्य है। मैंने सुपरफाइन, फाइन और मीडियम-ए कपड़ों की परिभाषा में भी परिवर्तन किया है जिससे लम्बे रेशे वाली कपास का इस्तेमाल ज्यादा हो सके जिसका उत्पादन अभी हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है। सूती धागे पर लगने वाले शुल्क की दरों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं और हथकरघा तथा विद्युत चालित करघों के क्षेत्रों को राहत दी गई है। हथकरघों की प्रतियोगितात्मक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत् चालित करघों पर संयुक्त कर की दरों को बढ़ा कर विद्युत् चालित करघा के क्षेत्र में होने वाले लाभ का कुछ अंश प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है। लेकिन इस संबंध में यह सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए सावधानी बरती गई है कि इसका छोटी यूनिटों पर कोई बुरा असर न पड़े। प्रत्येक यूनिट के पहले दो करघों पर लागू कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद के दो करघों में से प्रत्येक पर कर की दर 100 रुपये से बढ़ा कर 125 रुपये वार्षिक और बाकी करघों में से प्रत्येक पर कर की दर 200 रुपये से बढ़ा कर 250 रुपये वार्षिक कर दी गई है। इस युक्तिसंगत स्कीम से 2 करोड़ रुपये का मामूली राजस्व प्राप्त होगा।

2. 4. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि जब कभी कपड़ों की मांग मामूली सी बढ़ जाती है तब इस बात का ध्यान दिए बिना कि उत्पादन लागत बढ़ी है या नहीं खुदरा कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। यह लाभ बिचौलियों को होता है लेकिन इसका बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। ऐसे मामले प्रायः देखने में आते हैं जिन में व्यापारी वर्ग जिन कीमतों पर मिलों से कपड़े खरीवते हैं उनसे बहुत अधिक कीमतों पर उपभोक्ताओं के हाथ बेचते हैं। इससे समाज के अपेक्षाकृत गरीब लोगों का शोषण होता है जिन के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता और जिन्हें मौजूदा बाजार कीमतों की जानकारी भी नहीं होती। इस खुले अनाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था करने का फैसला किया है जिसके अन्तर्गत देश के बाजारों में उपभोक्ताओं के हाथ बेचे जाने वाले कपड़े के प्रत्येक मीटर की लम्बाई पर निर्माताओं को अनिवार्यतः अधिकतम खुदरा कीमत का ठप्पा लगाना पड़ेगा। इस फैसले को बहुत शीघ्र अमल में लाया जाएगा।

2. 5. मेरा अगला प्रस्ताव कागज और गत्ते के बारे में है जिन पर लंबे अरसे से मात्रानुसार शुल्क-दर लागू की जाती रही है। इसकी वजह से कुछ असंगतियाँ पैदा हो गई हैं जो मूल्य नियंत्रण को लागू करने के बाद और बढ़ गई हैं। अतः मैं कागज और गत्ते पर मौजूदा मात्रानुसार शुल्क के स्थान पर मूल्यानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुद्रण और लिखाई के कागज पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत तथा अन्य सभी कागजों और गत्तों पर 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कागज बनाने वाली मिलें शिक्षा के विभिन्न प्रयोजनों के लिए जैसे पाठ्य पुस्तकें आदि के प्रकाशन और सरकारी उपयोग के लिए जो सफेद कागज की सप्लाई अनुमोदित कीमतों पर करती हैं उस पर वी जाने वाली रियायत लगभग ज्यों की त्यों दी जाती रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुद्रण तथा लिखाई के अतिरिक्त और बादामी रंग के कागज पर जो 6 ग्राम से अधिक न हो, उस पर 15 प्रतिशत की रियायती दर से शुल्क लगेगा पर मुद्रण के कागज पर मौजूदा रियायती दरें कायम रहेंगी। इस उपाय से 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।

2. 6. अब मैं जिस वस्तु पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ वह है पेटेंट और मालिकाना हक वाली दवाएँ। मैं इन पर मूल्यानुसार 7.5 प्रतिशत की वर्तमान दर को बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत

कर देने का प्रस्ताव करता हूँ। चूंकि यह शुल्क भेषजकोषीय नामों से बेची जाने वाली दवाओं और बुनियादी भेषजों पर नहीं लगेगा इसलिए बढ़े हुए शुल्क का बोझ समाज के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध लोगों पर पड़ेगा। इस मद से 18.2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जीवन-रक्षी दवाओं पर मौजूदा 2.5 प्रतिशत की कम दर से कर लिया जाता रहेगा तथा सीरम टीका, और औषधि गर्भनिरोधक पर दी जाने वाली मौजूदा पूरी छूट जारी रहेगी।

2.7. मैंने सिगरेटों पर कर के ढांचे में थोड़ा सा फिर से समायोजन करने का प्रस्ताव किया है। कुछ अपवादों को छोड़ कर, सस्ते किस्म के सिगरेटों पर थोड़ी सी राहत मिलेगी और अन्य किस्मों के कुछ महंगे सिगरेटों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। मुझे ऐसा कोई औचित्य नहीं दिखाई देता कि जो लोग विभिन्न आंशों के ज्यादा कीमतों वाले सिगार और चुस्ट पीते हैं उन्हें इन चीजों के उत्पाद शुल्क के दायरे से अलग रख एक विशेष स्थिति का भोग करते रहने दिया जाए। मैं इन वस्तुओं पर उसी दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जो स्मॉकिंग मिक्सचर्स पर लागू है। इन परिवर्तनों से 12.2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.8. मैंने ब्लेंडेड फ्लेवोरिंग कंसंट्रेटों वाले एडरेटेड वाटर पर कर की दर बढ़ा दी है। सादे सोडे ग्रथवा एडरेटेड वाटर्स पर, जिनमें इस तरह के ब्लेंडेड फ्लेवोरिंग कंसंट्रेट नहीं होते, लगने वाले शुल्क की दर ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इस मद से 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

2.9. मैं पेंटों और वार्निशों, एंक्रोलिक फाइबर और एंक्रोलिक धागे, इलेक्ट्रानिक की कुछ चीजों और स्टार्च पर कर की दरों में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ। सीमेंट पर जो मूल्यानुसार शुल्क लगता है उसे प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बदल कर मात्रानुसार किया जा रहा है। इससे राजस्व में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टैरिफ की कुछ मदों में भी परिवर्तन किया जा रहा है जिनसे कोई विशेष अधिक राजस्व नहीं मिलेगा। इस सभी परिवर्तनों से कुल मिलाकर 9.8 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

2.10. वित्त अधिनियम 1975 के अन्तर्गत जो सहायक उत्पाद-शुल्क लगाया गया था वह 30 जून, 1976 तक वैध है। इसे 30 जून, 1977 तक जारी रखने का प्रस्ताव है।

2.11. वित्त मंत्री का काम केवल कर लगाना ही नहीं है बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि जब कोई उद्योग ग्रथवा उपभोक्ता भारी कठिनाई में हो तब वह उसे चयनात्मक आधार पर राहत भी प्रदान करे। मैं बिना लेरी वाले एल्यूमीनियम पर, जो अधिकतर वाणिज्यिक ग्रेड का होता है, शुल्क की दर में प्रति वर्ष 1200 रुपए प्रति टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस उपाय से एल्यूमीनियम की मांग बढ़ जाएगी और बिक्री भी बढ़ जाएगी। मैं कृत्रिम और सिंथेटिक रेजिन और प्लास्टिक की चीजों पर मूल्यानुसार लगने वाले शुल्क की 56 प्रतिशत की दर को घटा कर 40 प्रतिशत कर देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन चीजों से बने सामान पर भी उपयुक्त राहत दी जा रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह कदम उठाने से इन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं, तांबे पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर में भी 1400 रुपए प्रति टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को, जो सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है और जो देश में तांबे की एकमात्र उत्पादक है, ज्यादा लाभ होने लगेगा।

2.12. हमने ऊंची कीमतों और काले धन के खिलाफ जो कारगर कदम उठाए थे उनके परिणामस्वरूप कई उद्योगों विशेषतः टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में मांग

शुल्क में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। केप्रोलेक्टम, डी.एम.टी. और एकिलिक यार्न पर लगने वाले शुल्क में प्रस्तावित परिवर्तनों से 12.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.22. भारतीय टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में ऐसी अनेक मदें हैं जिनके सम्बन्ध में टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जी.ए.टी.टी.) के अन्तर्गत वचनबद्ध हैं कि हम उन पर लगने वाले शुल्क को एक खास परस्पर-सम्मत स्तर से ऊँचा नहीं होने देंगे। चूँकि हमने हाल में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 लागू किया है जिसमें मोटे तौर पर ब्रुसेल्स टैरिफ नामावली का अनुसरण किया गया है, इसलिए हमने जी.ए.टी.टी. परिषद् से सम्बद्ध संविदाकारी पक्षों के साथ बातचीत होने तक, करारों के अन्तर्गत अपने वचनों के सम्बन्ध में सामान्य छूट प्राप्त कर ली है। इसलिए इस कारण कुछ वस्तुओं को जो छूट प्राप्त है, मैं इस सामान्य छूट को देखते हुए उसे वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे 3 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

2.23. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मेरा सीमा शुल्कों से सम्बन्ध में कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव है। उर्वरक और अखबारी कागज के उद्योगों में नई पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के लिए मैं, उर्वरक कारखाने और अखबारी कागज के कारखाने लगाने के लिए विदेशों से मंगाई गई मशीनरी और उपकरणों के सीमा शुल्क दर को 40 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत **मूल्यानुसार** करने का प्रस्ताव करता हूँ। बाहर से मंगाए जाने वाले राफ फास्फेट पर लगने वाले सीमा शुल्क को भी घटाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल फास्फेटी और संयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन प्रस्तावों से राजस्व प्राप्ति में 13.15 करोड़ रुपए की कमी होगी।

2.24. मैं कम्प्यूटरों और छोटे कम्प्यूटरों के बुनियादी सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत **मूल्यानुसार** करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इन्हें सभी सहायक शुल्कों और प्रतिस्तुलनकारी शुल्कों से भी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। अन्य वस्तुएँ जिन्हें आयात शुल्क में राहत मिलेगी ये हैं : मेनेटिक टेप बनाने के लिए विदेशों से मंगाई जाने वाली पालिस्टर फिल्में, इलेक्ट्रानिक केपेसिटर बनाने के लिए आयात की जाने वाली मेटेलाइज्ड प्लास्टिक फिल्में और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल के लिए आयात किया जाने वाला खेलकूद का सामान। इन सभी वस्तुओं पर कुल मिलाकर 1.75 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

2.25. अब तक लगने वाले सहायक सीमा शुल्कों को 30 जून, 1977 तक जारी रखा गया है और इन शुल्कों की प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।

2.26. संघ उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों से 1976-77 में केन्द्र को कुल मिला कर 47.25 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

2.27. अब मुझे केवल दो प्रस्ताव और करने हैं जिनका लगभग सारा उद्देश्य राज्यों के लाभ के लिए साधन जुटाना है।

2.28. संघ सूची में उल्लिखित लिखतों जैसे रसीदों और हुण्डियों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्कों की दरों में काफी लम्बे समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं 1 जून, 1976 से कुछ मदों पर स्टाम्प शुल्कों की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। स्टाम्प शुल्कों की दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रति वर्ष 22.57 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

कर देने का प्रस्ताव करता हूँ। चूँकि यह शुल्क भेषजकोषीय नामों से बेची जाने वाली दवाओं और बुनियादी भेषजों पर नहीं लगेगा इसलिए बढ़े हुए शुल्क का बोझ समाज के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध लोगों पर पड़ेगा। इस मद से 18.2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जीवन-रक्षी दवाओं पर मौजूदा 2.5 प्रतिशत की कम दर से कर लिया जाता रहेगा तथा सीरम टीका, और औषधि गर्भनिरोधक पर दी जाने वाली मौजूदा पूरी छूट जारी रहेगी।

2. 7. मैंने सिगरेटों पर कर के ढाँचे में थोड़ा सा फिर से समायोजन करने का प्रस्ताव किया है। कुछ अपवादों को छोड़ कर, सस्ते किस्म के सिगरेटों पर थोड़ी सी राहत मिलेगी और अन्य किस्मों के कुछ महंगे सिगरेटों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। मुझे ऐसा कोई औचित्य नहीं दिखाई देता कि जो लोग विभिन्न ब्रांडों के ज्यादा कीमती वाले सिगार और चुरट पीते हैं उन्हें इन चीजों के उत्पाद शुल्क के दायरे से अलग रख एक विशेष स्थिति का भोग करते रहने दिया जाए। मैं इन वस्तुओं पर उसी दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जो स्मोकिंग मक्सचर्स पर लागू है। इन परिवर्तनों से 12.2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 8. मैंने ब्लेंडेड प्लेवरिंग कंसट्रेटों वाले एड्रेटेड वाटर पर कर की दर बढ़ा दी है। सादे सोडे अथवा एड्रेटेड वाटर्स पर, जिनमें इस तरह के ब्लेंडेड प्लेवरिंग कंसट्रेट नहीं होते, लगने वाले शुल्क की दर ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इस मद से 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

2. 9. मैं पेंटों और वार्निशों, एकीलिक फाइबर और एकीलिक धागे, इलेक्ट्रानिक की कुछ चीजों और स्टार्च पर कर की दरों में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ। सीमेंट पर जो मूल्यानुसार शुल्क लगता है उसे प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बदल कर मात्रानुसार किया जा रहा है। इससे राजस्व में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टैरिफ की कुछ मदों में भी परिवर्तन किया जा रहा है जिनसे कोई विशेष अधिक राजस्व नहीं मिलेगा। इस सभी परिवर्तनों से कुल मिलाकर 9.8 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

2. 10. वित्त अधिनियम 1975 के अन्तर्गत जो सहायक उत्पाद-शुल्क लगाया गया था वह 30 जून, 1976 तक वैध है। इसे 30 जून, 1977 तक जारी रखने का प्रस्ताव है।

2. 11. वित्त मंत्री का काम केवल कर लगाना ही नहीं है बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि जब कोई उद्योग अथवा उपभोक्ता भारी कठिनाई में हो तब वह उसे चयनात्मक आधार पर राहत भी प्रदान करे। मैं बिना लेखी वाले एल्यूमीनियम पर, जो अधिकतर वाणिज्यिक ग्रेड का होता है, शुल्क की दर में प्रति वर्ष 1200 रुपए प्रति टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस उपाय से एल्यूमीनियम की मांग बढ़ जाएगी और विक्री भी बढ़ जाएगी। मैं कृत्रिम और सिंथेटिक रेजिन और प्लास्टिक की चीजों पर मूल्यानुसार लगने वाले शुल्क की 56 प्रतिशत की दर को घटा कर 40 प्रतिशत कर देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन चीजों से बने सामान पर भी उपयुक्त राहत दी जा रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह कदम उठाने से इन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं, तांबे पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर में भी 1400 रुपए प्रति टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को, जो सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है और जो देश में तांबे की एकमात्र उत्पादक है, ज्यादा लाभ होने लगेगा।

2. 12. हमने ऊँची कीमतों और काले धन के खिलाफ जो कारगर कदम उठाए थे उनके परिणामस्वरूप कई उद्योगों विशेषतः टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में मांग

घट' गई है। इन में से कुछ कारखानों ने कामगरों की अस्थायी छंटनी कर दी है जिससे उनके लिए कई कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं। यदि हमने स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की तो इस बात का खतरा है कि कई और औद्योगिक कारखाने बन्द हो जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में कामगरों की छंटनी हो जाएगी। इन उद्योगों को अपने उत्पादन में विविधता लाने या विदेशों में प्रतियोगिता करने के योग्य बनने में कुछ समय लगेगा। इस बीच यह जरूरी है कि उत्पाद शुल्कों में कुछ फेर-बदल किए जाएं जिससे कि ये उद्योग जिंदा बने रह सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उन टेलीविजन सेटों के सम्बन्ध में, जिनकी यूनिट कीमत 1800 रुपए से अधिक न हो, शुल्क की 20 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर को घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर उद्योगों को भी राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ। मध्यम आकार के उन रेफ्रिजरेटरों पर, जिनकी क्षमता 165 लीटर से अधिक न हो, लगने वाले शुल्क को 50 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। औद्योगिक प्रयोजनों और कोल्ड स्टोरेज के प्रयोजनों और कुछ खास खास प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग मशीनरी पर 20 प्रतिशत की गिरायती दर से शुल्क लगेगा जो मौजूदा दरों की अपेक्षा बहुत कम है। वाटर कूलरों के मामले में भी राहत दी जा रही है। मैं 16 से कम हार्स-पावर वाली आर०ए०सी० रेटिंग पैसेंजर कारों के मूल्यानुसार शुल्क को 5 प्रतिशत कम करने का और टायरों, ट्यूबों और बैटरियों को उस समय शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ, जब वे इन कारों के साथ मूल उपस्कर के रूप में सप्लाई की जाएं। जीपों, एम्बुलेंसों, पिक अप वनों और 16 से कम हार्स पावर वाली अन्य गाड़ियों के मूल्यानुसार शुल्क की दर को भी 5 प्रतिशत कम किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि मोटर लगे साइकिल रिकशाओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।

2.13. मैं कैप्रोलेक्टम के शुल्क को 50 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का और विस्कोस और ऐसीटेट सूत पर जिससे अपेक्षाकृत सस्ते कपड़े का उत्पादन होता है लगने वाले शुल्क में कुछ कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं सर्वसाधारण के उपयोग की कई वस्तुओं जैसे घर में कपड़े धोने का साबुन और नहाने का सस्ती किस्मों का साबुन, डीटरजेंटों और स्टेनलेस स्टील के ब्लेडों के उत्पाद शुल्कों में राहत देना चाहता हूँ। जीवनयापन स्तर के आमतौर पर ऊंचा हो जाने से टेबुल और पेडेस्टल पंखों का इस्तेमाल लगभग सभी वर्गों द्वारा किया जाता है; यही हालत सर्वव्यापी ट्रांजिस्टरों और टाचों के ड्राई सेलों की है। इसलिए मैं इन वस्तुओं को कुछ राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ।

2.14. निर्यात-संवर्धन के उपाय के रूप में, मैं सिले-सिलाए कपड़ों पर लगने वाले शुल्क को हटाने और चाय सम्बन्धी छूट स्कीम में कुछ फेर-बदल करने का प्रस्ताव करता हूँ। जोन III में चाय की उत्पादन-लागत अधिक होने और इसकी उपज कम होने के कारण इस जोन में पैदा की जाने वाली चाय को भी कुछ राहत दी जा रही है।

2.15. उत्पादन में वृद्धि करने को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद शुल्कों में राहत देने की एक नई स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस स्कीम के अनुसार कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी चुने हुए आधार वर्ष में हुए उत्पादन से अधिक उत्पादित वस्तुओं पर देय शुल्क के 25 प्रतिशत तक राहत दी जा सकेगी। इस स्कीम का ब्यापार तैयार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि शुरू में यह स्कीम एक वर्ष के लिए लागू की जाएगी।

2. 16. उत्पाद शुल्कों की दरों में परिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप 50 करोड़ रुपये की राहत देने के बाद केवल 15. 12 करोड़ रुपये की निवल प्राप्तियां होंगी। इन में से केन्द्र को केवल 8. 55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और राज्यों के हिस्से की राशि 6. 57 करोड़ रुपये की होगी। मुझे कोई सन्देह नहीं कि उत्पाद शुल्कों में जो भारी रियायतें दी गई हैं, उपभोक्ता उनका स्वागत करेंगे।

2. 17. मैं अब सीमा शुल्कों की ओर आता हूँ। जिन मामलों में मैंने सीमा शुल्कों की दरों में वृद्धि की है उनमें मैंने केवल उन वस्तुओं की चुना है जिनसे भारतीय उद्योगों की गति मिलेगी या जिनसे भारी प्रोमियम मिलता है, जिसमें सरकारी कोष को अपना उचित हिस्सा पाने का अधिकार है।

2. 18. विदेशों से मंगाई जाने वाली स्टेनलेस स्टील की चादरों पर भारतीय बाजारों में बहुत लाभ कमाया जाता है; इसका कुछ कारण यह है कि देश में इनकी कमी है और कुछ, कारण यह है कि विदेशों से मंगाई जाने वाली स्टेनलेस स्टील की चादरों और देश में उत्पादित चादरों की कीमतों के बीच बड़ा भारी अन्तर है। इसलिए मैं इस वस्तु पर, लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क की मौजूदा 220 प्रतिशत दर को बढ़ा कर 320 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा स्टेनलेस स्टील की प्लेटों और पट्टियों पर लगने वाले शुल्क की 75 प्रतिशत की मौजूदा मूल्यानुसार दर को बढ़ा कर 120 प्रतिशत कर देने का भी प्रस्ताव है। स्टेनलेस स्टील की चादरों, प्लेटों और पट्टियों के सीमा शुल्क में प्रस्तावित वृद्धियों से कुल मिलाकर 10. 60 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 19. देश के अन्दर हाई कार्बन इस्पात और मिश्रधातु इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने और देश में उत्पादित लोहे और इस्पात के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए और राजस्व जुटाने के उपाय के रूप में हाई कार्बन इस्पात और मिश्रधातु इस्पात पर (स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क की दर को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय लोहे और इस्पात पर लगने वाले प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क के सम्बन्ध में जो रियायत दी जाती है, मैं उसमें संशोधन करने का और बुनियादी उत्पाद शुल्क की राशि के बराबर प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इन परिवर्तनों से 18. 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. 20. चूकि तांबे की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और देश के अन्दर की कीमतों में काफी अन्तर है, इसलिए मैं तांबे के सीमा शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। तांबे की टैरिफ दर को 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाएगा। लेकिन, फिलहाल मैं तांबे पर लगने वाले सीमा शुल्क की प्रभावी दर को 60 प्रतिशत मूल्यानुसार निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रभावी सन्तुलनकारी शुल्क को, जो इस समय 5,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन है, बढ़ा कर 5,600 रुपये प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है। तांबे के स्क्रेप और तांबे से बनी वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क में, आवश्यक समायोजनों सहित, तदनु रूप परिवर्तन किए जा रहे हैं। तांबे, तांबे से बनी वस्तुओं और तांबे के स्क्रेप से सम्बन्धित प्रस्तावित परिवर्तनों से 6. 65 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

2. 21. इन्हीं कारणों से मैं केप्रोलेक्टम और डीमेथिल टरेफथेलेट (डी.एम.टी.) के आयात शुल्क की 75 प्रतिशत की मौजूदा दर को बढ़ाकर 120 प्रतिशत करने और केप्रोलेक्टम को प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से मिलने वाली छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं एफ्लिक यान के बुनियादी उत्पादन

शुल्क में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। केप्रोलेक्टम, डी.एम.टी. और एक्जिलिक यार्न पर लगने वाले शुल्क में प्रस्तावित परिवर्तनों से 12.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.22. भारतीय टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में ऐसी अनेक मदें हैं जिनके सम्बन्ध में टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जी.ए.टी.टी.) के अन्तर्गत वचनबद्ध हैं कि हम उन पर लगने वाले शुल्क को एक खास परस्पर-सम्मत स्तर से ऊँचा नहीं होने देंगे। चूँकि हमने हाल में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 लागू किया है जिसमें मोटे तौर पर ब्रुसेल्स टैरिफ नामावली का अनुसरण किया गया है, इसलिए हमने जी.ए.टी.टी. परिषद् से सम्बद्ध संविदाकारी पक्षों के साथ बातचीत होने तक, करारों के अन्तर्गत अपने वचनों के सम्बन्ध में सामान्य छूट प्राप्त कर ली है। इसलिए इस कारण कुछ वस्तुओं को जो छूट प्राप्त है, मैं इस सामान्य छूट को देखते हुए उसे वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे 3 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

2.23. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मेरा सीमा शुल्कों से सम्बन्ध में कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव है। उर्वरक और अखबारी कागज के उद्योगों में नई पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के लिए मैं, उर्वरक कारखाने और अखबारी कागज के कारखाने लगाने के लिए विदेशों से मंगाई गई मशीनरी और उपकरणों के सीमा शुल्क दर को 40 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। बाहर से मंगाए जाने वाले राक फास्फेट पर लगने वाले सीमा शुल्क को भी घटाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल फास्फेटी और संयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन प्रस्तावों से राजस्व प्राप्ति में 13.15 करोड़ रुपए की कमी होगी।

2.24. मैं कम्प्यूटरों और छोटे कम्प्यूटरों के बुनियादी सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इन्हें सभी सहायक शुल्कों और प्रतिस्तुलनकारी शुल्कों से भी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। अन्य वस्तुएँ जिन्हें आयात शुल्क में राहत मिलेगी ये हैं : मैग्नेटिक टेप बनाने के लिए विदेशों से मंगाई जाने वाली पॉलिस्टर फिल्में, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर बनाने के लिए आयात की जाने वाली मेटेलाइज्ड प्लास्टिक फिल्में और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल के लिए आयात किया जाने वाला खेलकूद का सामान। इन सभी वस्तुओं पर कुल मिलाकर 1.75 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

2.25. अब तक लगने वाले सहायक सीमा शुल्कों को 30 जून, 1977 तक जारी रखा गया है और इन शुल्कों की प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।

2.26. संघ उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों से 1976-77 में केन्द्र को कुल मिला कर 47.25 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

2.27. अब मुझे केवल दो प्रस्ताव और करने हैं जिनका लगभग सारा उद्देश्य राज्यों के लाभ के लिए साधन जुटाना है।

2.28. संघ सूची में उल्लिखित लिखतों जैसे रसीदों और हुण्डियों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्कों की दरों में काफी लम्बे समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं 1 जून, 1976 से कुछ मदों पर स्टाम्प शुल्कों की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। स्टाम्प शुल्कों की दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रति वर्ष 22.57 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों और संघ को क्रमशः 18.44 करोड़ रुपए और 37 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि शुल्क की नई दरें वित्तीय वर्ष के केवल एक भाग के लिए ही प्रभावी होंगी ।

2.29. मैं ने जिस एक अन्य परिवर्तन का प्रस्ताव किया है वह है अल्कोहल, मादक दवाओं और मादक द्रव्यों से युक्त औषधियों और प्रसाधन-वस्तुओं के उत्पाद शुल्कों की दरों में तब्दीली और कुछ शब्दों की परिभाषा में संशोधन, जिनमें मादक दवाएं और मादक द्रव्य शामिल हैं । राज्य सरकारों ने यह कहा है कि हालांकि अल्कोहल पर लगने वाले राज्य उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की गई थी, लेकिन उक्त औषधियों और प्रसाधन वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों में 1964 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इससे इन औषधियों का दुरुपयोग होता है । इसलिए मैं अल्कोहल, मादक दवाओं और मादक द्रव्यों से युक्त औषधियों और प्रसाधन-वस्तुओं के उत्पाद शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे प्रति वर्ष लगभग 7.5 से 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । इस राशि में से केन्द्र को संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में 50 लाख रुपया और शेष धन राज्यों को प्राप्त होगा ।

III

3.1. ऊपर मैं ने जिन उपायों की रूपरेखा दी है उनके परिणामस्वरूप करों के रूप में केन्द्र को 48 करोड़ रुपए की और राज्यों को 32 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवल प्राप्ति होगी । इस प्रकार बजट में 368 करोड़ रुपए का घाटा जिसका पहले संकेत किया गया है, कम होकर 320 करोड़ रुपए रह जाएगा । मैं इस घाटे को इसी रूप में छोड़ देने का प्रस्ताव करता हूँ । यह मेरी धारणा है कि इतने घाटे से अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों में वृद्धि नहीं होगी । फिर भी आर्थिक गतिविधियों के भविष्य के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । हम अर्थ व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहेंगे ।

3.2. मनुष्य की तरह राष्ट्र के जीवन में भी ज्वार आता है जिसके साथ चल पड़ने पर ही भाग्य का निर्माण होता है । आज राष्ट्र इस ज्वार के उत्कर्ष पर है । अर्थ व्यवस्था आगे वृद्धि करने के लिए सन्नद्ध है । आपात स्थिति और नए आर्थिक कार्यक्रम ने आर्थिक वातावरण में एक नवीन परिवर्तन का सूत्रपात कर दिया है । हमें चाहिए कि हम इन अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाएं और आर्थिक व सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में नवीन गति भर दें ।

इन प्रस्तावों को बनाते समय मेरा ध्यान राष्ट्रपिता द्वारा बताए गए महान राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर जा रहा है कि हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें न किसी के पास कम हो न किसी के पास ज्यादा ।

महोदय, मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक सदन से अनुरोध करता हूँ कि वह इस बजट को स्वीकार करने की कृपा करे ।

PART 'B' OF THE BUDGET SPEECH 1976-77

DIRECT TAXES

1.1. I now turn to direct tax proposals.

1.2. As Hon'ble Members will recall, the rates of income-tax on personal incomes were reduced in 1974 on the basis of a recommendation of the Direct

Taxes Enquiry Committee. While presenting the Budget for 1974-75, my distinguished predecessor had expressed the hope that the reduction in rates would lead to better tax compliance. This expectation has been fulfilled and is reflected in the striking increase in income-tax collections during the last two years. While some other factors including the relentless drive against tax evaders and other economic offenders have played a part in improving collections, it is also obvious that the reduction in tax rates has played a major role in promoting far better tax compliance. The remarkable response to the voluntary disclosure scheme, where the maximum rate was 60 per cent, lends considerable support to the judgement that the majority of Indian tax-payers would prefer to abide by the law and pay taxes as due, provided the tax burden is reasonable. I, therefore, propose to reduce the rates of taxes on personal incomes and wealth. The maximum marginal rate of income-tax including surcharge will be reduced from 77 per cent to 66 per cent and will be applicable on the slab of income over Rs. 1,00,000 in the case of individuals and Hindu undivided families, other than those having one or more members with independent income exceeding the exemption limit. I do not, however, anticipate any loss of revenue on this account, as the whole logic of the present exercise in rationalisation of tax rates is that it will evoke better compliance on the part of the assesseees.

1.3. In order to raise resources for financing the Plan and also reduce inflationary pressures generated by larger disposable incomes in the hands of income-tax assesseees, I, however, propose to continue the compulsory deposit scheme for income-tax payers for another year. While the rate of compulsory deposit on current incomes up to Rs. 25,000 will remain at the existing level of 4 per cent, the rate on the slab from Rs. 25,001 to Rs. 70,000 will be raised from 6 per cent to 10 per cent; on the slab over Rs. 70,000 the rate will be increased from 8 per cent to 12 per cent. Resources to the tune of Rs. 80 crores will accrue in 1976-77 as a result of this measure. The honest tax-payer who gets some long overdue relief should not grudge this contribution to national savings.

1.4. It is well known that the prevailing high rates of wealth-tax provided a powerful incentive for undervaluation and widespread evasion of taxes. In regard to wealth-tax, in the case of individuals and Hindu undivided families, other than those having one or more members with independent wealth exceeding Rs. 1,00,000, the new rate of wealth-tax on the initial slab of net wealth up to Rs. 5,00,000 will now be $\frac{1}{2}$ per cent; $1\frac{1}{2}$ per cent on the slab from Rs. 5,00,001 to 10,00,000; 2 per cent on the slab from Rs. 10,00,001 to Rs. 15,00,000 and $2\frac{1}{2}$ per cent on the slab over Rs. 15,00,000. At the same time, I propose to reduce the exemption limit in respect of wealth-tax in the case of all Hindu undivided families from Rs. 2,00,000 to Rs. 1,00,000. The additional wealth-tax currently levied in respect of urban lands and buildings has lost its rationale in view of the ceiling on urban vacant land and other measures in regard to urban property, and is proposed to be discontinued.

1.5. At existing rates, the combined incidence of income-tax and wealth-tax works out to more than 100 per cent of income at certain levels. The present structure has been found to be unrealistic. These high rates have not led to any significant reduction of inequality of income and wealth. On the contrary, they have resulted in large scale tax evasion, generation of black money, and conversion of visible assets into invisible ones. It is essential to remove these distortions in the economy. The reduction in wealth-tax rates should not over a period lead to any loss of revenue. This rationalisation of tax structure is in the nature of an experiment. It is my hope that with better compliance on the part of the assesseees and more efficient administration, we can raise more resources.

1.6. In order to remove the hardship faced by owners of self-occupied property who are now required to furnish its fair market value in the return of net wealth every year, it is proposed to freeze the value of one self-occupied house property at the value adopted for the year in which the property is constructed or acquired by the assessee, or for the year 1971-72, whichever is later.

1.7. Hon'ble Members are aware that the Hindu undivided family is often used as a medium for tax avoidance. I have, therefore, proposed withdrawal of certain concessions currently available in computing the taxable income of Hindu undivided families having at least one member with an independent income exceeding the exemption limit.

1.8. Authors, playwrights, artists, musicians and actors do not earn steady incomes over the period of their professional career. In order to enable them to

moderate their tax liability during years when they earn high incomes, I propose to increase the monetary ceiling limit for these categories in respect of qualifying savings through Life Insurance, Cumulative Time Deposits, Public Provident Fund, etc., from Rs. 25,000 to Rs. 50,000 a year.

1.9. I shall now deal with the corporate sector. I have already drawn attention to the sharp increase in capital costs that has taken place. This has not only prevented faster expansion of capacity, but has also imposed considerable strain on existing undertakings which are obliged to replace worn-out and obsolete equipment. Unless the corporate sector is enabled to provide adequately for renewals and renovation, employment and industrial growth will be jeopardised. Fiscal policy should therefore be oriented to provide the necessary stimulus for the growth and modernisation of the corporate sector. I have, therefore, decided to introduce a scheme of investment allowance for certain priority industries. The present scheme of initial depreciation allowance will be replaced by a system of investment allowance. The investment allowance will be allowed at the rate of 25 per cent of the cost of acquisition of new machinery and plant installed after 31st March, 1976 in industries currently qualifying for initial depreciation. I also propose to extend the list of qualifying industries by including eight other priority or export-oriented industries, namely, carbon and graphite products; inorganic heavy chemicals; organic heavy chemicals; synthetic rubber and rubber chemicals, including carbon black; industrial explosives; basic drugs; industrial sewing machines and finished leather and leather goods, including footwear made wholly or substantially of leather. I may, however, draw the attention of the House to certain basic differences between the investment allowance now proposed and the earlier development rebate. The investment allowance will be withdrawn and will become liable to tax if this reserve is not utilised for the purpose of acquiring new machinery or plant within a period of ten years. No part of it will be available for distribution as profits. The present scheme of investment allowance will facilitate investment in priority industries and reduce the dependence of the corporate sector on public financial institutions.

1.10. As Hon'ble Members are aware, a surcharge of 2½ per cent on income-tax was levied on companies in 1971 at the time of the Bangladesh crisis. In 1972, this surcharge was raised to 5 per cent. I proposed to exempt those companies which will deposit an equivalent amount with the Industrial Development Bank of India for a period of five years, from this surcharge. This measure will ensure that the funds rotate and are available to the corporate sector for investment. I also propose to reduce the rates of capital gains tax in respect of long-term capital gains derived by companies.

1.11. As a result of increase in the interest rates, the return on safe investments has gone up considerably in recent years. In order to make risk bearing investment in shares of companies more remunerative, I propose to raise the threshold for the determination of chargeable profits under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 from 10 per cent to 15 per cent of the capital employed. The new threshold will, however, be reckoned with reference to the owned capital of the company and will exclude long-term borrowings and debentures.

1.12. It has been urged that the present high rates of interest have a dampening effect on investment and production. The present structure of interest rates is an integral part of our credit policy which has helped in keeping inflationary pressures under control. However, taking note of the escalation in costs of industrial projects, I propose to exempt interest received by scheduled banks on long-term loans granted to industry for the purchase of capital plant and machinery from interest tax levied under the Interest-tax Act, 1974. As this House will recall, the tax on interest was conceived essentially as a regulatory measure.

1.13. The present system of taxation of foreign companies gives rise to several administrative difficulties and uncertainties. As a measure of simplification, I propose to levy income-tax at a flat rate of 40 per cent on the gross amount of royalties received by them from Indian concerns under approved agreements made after 31st March, 1976. Lumpsum payments received by such companies for providing technical know-how outside India under approved agreements will be charged to tax at a flat rate of 20 per cent of the gross amount received by them. Royalties and technical service fees received by foreign companies under existing agreements will continue to be charged on the existing basis, subject to the modification that the expenditure incurred for earning such income will be limited to 20 per cent of the gross payments.

1.14. Dividends received by foreign companies will be charged to tax at a flat rate of 25 per cent on the gross amount of such dividends. Further, head office expenses allowable as deduction against Indian profits will be subject to specified ceiling limits the deduction on account of such expenses will broadly be limited to 5 per cent of the Indian income.

1.15. With a view to simplifying the procedure for taxation of the income of the Life Insurance Corporation of India, I propose to provide that the taxable profits of life insurance business will be taken at the figure of the annual average of the surplus disclosed by the actuarial valuation made in accordance with the Insurance Act, 1938. Such profits will be charged to tax at the rate of 12½ per cent.

1.16. There is acute shortage of housing, particularly of the kind required by the poorer sections of the community. House construction is entitled to be treated as a major industry in its own right. Apart from fulfilling the basic human need for shelter, it generates considerable employment both direct and indirect. Increased activity in this sector will also improve the demand for materials like cement, steel and coal for making bricks. To attract more resources for this neglected but essential purpose, I propose to exempt new dwelling units put up after 1st April, 1976 with a pith area upto 80 sq. meters from wealth-tax for a period of five years. Initial depreciation allowance of 20 per cent will hereafter be available in respect of houses constructed by employers for use as residences of low-paid employees having annual salary incomes up to Rs. 10,000 instead of Rs. 7,500 as at present.

1.17. As a measure for augmenting foreign exchange resources, I propose to exempt from income-tax, interest payable by industrial undertakings in India on foreign exchange loans under approved agreements. I also propose to exempt from wealth-tax, investment by non-resident Indians in equity shares of certain priority and export-oriented industries. Indians returning from abroad will be exempt for seven years from wealth-tax in respect of their savings abroad repatriated to India.

1.18. It is our judgement that the various direct tax concessions will be off-set by better tax compliance and improved administration.

II

INDIRECT TAXES

2.1. I shall now deal with proposals relating to indirect taxes.

2.2. Before framing this year's Budget, I had the benefit of consultations with experts drawn from various fields and representatives of industry and commerce. I am grateful to them for the several valuable suggestions made by them to which I have given careful consideration. During the course of the year I have had a detailed review made of the excise duty structure, which has highlighted certain areas for improvement. In particular, the feasibility of adopting some form of value added tax has been studied. Since the issues arising from the studies undertaken are highly complex and have far reaching effects, I propose to appoint a Committee to review the existing structure of the indirect tax system and advise the Government on the steps to be taken.

2.3. I shall now deal with specific proposals relating to excise duties. At present, excise duties on cotton fabrics are specific and their incidence does not depend on the price of the fabric. Though the present rates are highly complex and are graded both on the basis of average counts, and according to the various processes to which cotton fabrics can be subjected, the burden of excise duties has not been equitably distributed. There are also considerable difficulties in administering these tariffs in an industry with many varietal differences. A reform of this system has, therefore, been long overdue and I have now decided to switch over to a system of *ad valorem* duties on cotton fabrics. This will give relief to the weaker and more vulnerable sections of society who consume lower priced varieties of cloth and will shift the burden to those who have the ability to pay the higher prices for superior varieties of cloth. I have also made changes in the definition of superfine, fine and medium A fabrics to stimulate the use of long staple cotton, the production of which has risen substantially in recent years. Certain changes have also been made in the duty rates on cotton yarn, and relief has been given to the handloom and powerloom sectors. At the same time, handlooms are facing serious competition from powerlooms resulting in a large accumulation of unsold handloom cloth. We have to provide a measure of protection to the handloom industry against the competition from powerloom. I, therefore, propose to increase the rates of compounded levy on powerlooms. I have taken care to ensure that small powerloom owners are not affected. The rate on the first two looms in each unit will therefore remain unchanged. On the next two looms the rate will be raised from Rs. 100 to Rs. 125 per loom per year, and on the

remaining looms from Rs. 200 to Rs. 250 per loom per year. The net result of the rationalisation scheme will be a marginal gain in revenue of Rs. 2 crores.

2.4. Honble Members are aware that in the textile trade whenever there is a slight pick up in demand, retail prices are raised without any relation to changes in the cost of production. The benefit accrues to middlemen at the consumers' expense. Cases are also frequent of traders selling at much higher prices than those at which they purchase from the mills. This results in exploitation of the poorer sections of society who do not have much choice in purchasing their requirements of cloth and are not well informed about prevailing market prices. In order to do away with these obvious malpractices, Government have decided to make it obligatory for the manufacturers to stamp the maximum retail price on every metre of cloth for sale to consumers in the domestic market. This decision will be implemented expeditiously.

2.5. My next proposal relates to paper and paper board, which have been assessed at specific duty rates for a long time. As a result of this, certain anomalies have crept in which have been accentuated after price decontrol. I, therefore, propose to replace the present specific duties on paper and paper board by *ad valorem* duties. Printing and writing paper will be subject to a duty of 25 per cent *ad valorem* and all other paper and paper board to a duty of 30 per cent *ad valorem*. I would, however, like to make it clear that the concessional duty now available to white printing paper which is supplied by paper mills at the agreed price for various educational purposes, such as production of text-books and exercise books, and for Government use, will continue practically unchanged. Unbleached and Badami printing and writing paper of substance not exceeding 65 gms. will also be subject to a concessional rate of 15 per cent duty, while existing concessions for newsprint will be continued. The additional yield from this measure will be Rs. 13 crores.

2.6. The next item on which I propose to step up excise duty is patent and proprietary medicines. I propose to raise the duty from the existing level of 7.5 per cent to 12.5 per cent *ad valorem*. Since this duty will not apply to medicines sold under pharmacopoeial names and basic drugs, the burden of the increased duty will be borne only by relatively affluent sections of the society. The additional revenue from this item will be Rs. 18.2 crores. I may also mention that the present lower rate of duty of 2.5 per cent on life saving drugs and complete exemption admissible to sera, vaccine and medicinal contraceptives will remain unchanged.

2.7. I have proposed some readjustments in the duty structure on cigarettes. With a few exceptions, there will be some relief to cheaper brands of cigarettes and additional imposition on some other costlier brands. I see no justification for the privilege enjoyed by the smoker of high priced cigars and cheroots sold under brand names of being exempt from the purview of the excise levy. I propose to tax these at the same rate as smoking mixtures. The additional revenue derived from these changes will be Rs. 12.2 crores.

2.8. I have raised the duty on aerated waters containing blended flavouring concentrates. There will be no change in the duty on plain soda or aerated waters which do not contain such blended flavouring concentrates. This measure will yield a revenue of Rs. 8 crores.

2.9. I am also making some changes in the duty on paints and varnishes, acrylic fibre and acrylic yarn, certain electronic items and starch. The *ad valorem* duty on cement is being converted to a specific duty for administrative convenience. The revenue implications of these are marginal. A few changes are also being made in the description of certain tariff items which will not yield any significant additional revenue. All these changes, when taken together, will yield Rs. 9.8 crores.

2.10. The auxiliary duty of excise levied under the Finance Act, 1975 was valid upto 30th June, 1976. It is proposed to continue this up to 30th June, 1977.

2.11. The Finance Minister's role is not that of a mere tax-gatherer; he has also to provide relief selectively, when any section of the industry or the consumers is in serious difficulty. I propose to reduce the duty on non-levy aluminium which is mostly of the commercial grade by Rs. 1,200 per tonne. This will, I am confident, improve the off-take of accumulated stocks by stimulating demand. I also propose to reduce the duty on artificial and synthetic resins and plastic

materials from the present level of 56 per cent to 40 per cent *ad valorem*. Appropriate relief is also being given to articles made from these materials. I expect that this step will induce larger production of these materials. I also propose to reduce the duty on copper by Rs. 1,400 per tonne. This will help to improve the profitability of Hindustan Copper Ltd., a public sector undertaking, which is the only producer in this field in our country.

2.12. Our effective action against inflation and black money has resulted in demand recession in some industries, particularly those producing consumer durables. Some of these units have already laid off workers causing considerable hardship. Unless we take remedial action, there is risk of more industrial units closing down or laying off large number of workers. These industries can diversify into new lines of production or become competitive abroad only over a period of time. In the meanwhile, it is essential to enable them to survive by effecting some adjustments in excise duties. Keeping this in view, I propose to reduce the duty on television sets whose unit value does not exceed Rs. 1,800 from 20 per cent to 5 per cent *ad valorem*. I also propose to give relief to the refrigerating and air-conditioning industry. The duty on medium sized refrigerators of capacity not exceeding 165 litres is being reduced from 50 per cent to 40 per cent. Refrigerating and air-conditioning machinery used for industrial, cold storage and certain preferred purposes will be granted a concessional rate of duty of 20 per cent which is significantly lower than the existing rates. Relief is also being given in the case of water coolers. I propose to reduce the duty on passenger cars of less than 16HP (RAC rating) by 5 per cent *ad valorem*, and also grant exemption from duty on tyres, tubes and batteries when these are supplied as original equipment with the cars. The duty on jeeps, ambulances, pick-up vans and other vehicles of less than 16 HP is also being reduced by 5 per cent *ad valorem*. Hon'ble Members will be happy to know that motorised cycle rickshaws are being exempted from excise duty.

2.13. I propose to reduce the duty on caprolactam from 50 per cent to 25 per cent *ad valorem* and make some reductions on viscose and acetate yarns which go into the production of relatively cheap fabrics. I propose to give relief by way of excise duty to a number of common consumer items, *viz.*, household laundry and cheaper varieties of toilet soap, detergents and stainless steel blades. With rising living standards generally, table and pedestal fans of small size are used by almost all sections; so are dry cells for the ubiquitous transistor and torchlight. I, therefore, propose to give some relief to these items.

2.14. As an export promotional measure, I propose to abolish the excise duty on ready-made garments and to make some adjustments in the tea rebate scheme. Some relief is also being given to tea produced in Zone III because of the high cost of production and the low yield.

2.15. It has been decided to introduce a new scheme of excise duty relief to encourage higher production. The scheme visualises grant of relief in respect of selected commodities to the extent of 25 per cent of duty payable on goods produced in excess of production in a selected base year. Details of the scheme are now being worked out and I expect that it will be introduced for one year in the first instance.

2.16. The effect of changes in excise rates will amount to a net realisation of only Rs. 15.12 crores, after allowing reliefs of the order of Rs. 50 crores. Of this, the additional revenue accruing to the Centre will be Rs. 8.55 crores, while the States' share will be Rs. 6.57 crores. I have no doubt that the consumer will welcome the substantial reliefs.

2.17. I now deal with Customs duties. Where I have increased the rates of Customs duties, I have selected those items which will either give an added impetus to domestic industry or where large premia prevail, the Exchequer being entitled to its rightful share.

2.18. Imported stainless steel sheets have been commanding high premia in the Indian market, partly because of scarcity and partly because of large differential between the prices of imported and indigenously produced stainless steel sheets. I, therefore, propose to raise the import duty on this item from the present level of 220 per cent to 320 per cent *ad valorem*. I also propose to raise the import duty on stainless steel plates and strips from the present level of 75 per cent to 120 per cent *ad valorem*. The proposed increase in the import duty on stainless steel sheets, plates and strips will together yield an additional revenue of Rs. 10.60 crores.

2.19. With a view to encouraging greater production of high carbon and alloy steel within the country and larger use of indigenously produced iron and steel, and also as a revenue raising measure, I propose to increase the existing import duty on high carbon and alloy steel (other than stainless steel) from 35 per cent to 75 per cent *ad valorem*. I also propose to modify the existing concession with regard to countervailing duty on iron and steel and fix countervailing duty at an amount equal to the basic excise duty. These changes will yield an additional revenue of Rs. 18.40 crores.

2.20. As there is a wide gap between the international price of copper and the indigenous price, I propose to increase the import duty on copper. The tariff rate on copper will be raised from 40 per cent to 100 per cent *ad valorem*. However, for the present, I propose to fix the effective import duty on copper at 60 per cent *ad valorem*. The effective countervailing duty which is now Rs. 5,000 per metric tonne is being stepped up to Rs. 5600 per metric tonne. Corresponding changes are also being made with necessary adjustments in the import duty and countervailing duty on copper scrap and copper manufactures. The proposed changes on copper and copper manufactures and copper scrap will yield a revenue of Rs. 6.63 crores.

2.21. For similar reasons, I propose to increase the import duty on caprolactam and Dimethyl terephthalate (D.M.T.) from the present level of 75 per cent to 120 per cent and to withdraw the exemption from countervailing duty on caprolactam. I also propose to increase the basic customs duty on acrylic yarn by Rs. 20 per kilogram. The proposed changes in duty on caprolactam, D.M.T. and acrylic yarn will yield an additional revenue of Rs. 12.85 crores.

2.22. There are a number of items in the first Schedule to the Indian Tariff Act in respect of which we have international commitments under the General Agreement on Tariffs and Trade to maintain the duty at points not exceeding certain agreed levels. Since we have recently enacted the Customs Tariff Act, 1975 which follows broadly the Brussels Tariff Nomenclature, we have obtained a general waiver from the G.A.T.T. Council in regard to our commitments under the Agreements, pending renegotiation with the concerned contracting parties. In view of this waiver I propose to withdraw the exemption enjoyed by certain articles on this account, which will yield revenue of Rs. 3 crores.

2.23. There are a few areas in which I propose to give some concessions with regard to customs duties. With a view to encourage new investment in the fertiliser and newsprint industries, I propose to reduce the duty on machinery and equipment imported for setting up fertiliser plants and newsprint plants from 40 per cent to 30 per cent *ad valorem*. The customs duty on imported rock phosphate used for manufacture of phosphatic and complex fertilisers is also being withdrawn. These measures will involve a revenue loss of Rs. 13.15 crores.

2.24. On computers and computer sub-systems I propose to reduce the basic import duty from 60 per cent to 40 per cent *ad valorem*. I also propose to exempt these from the whole of the auxiliary duty and countervailing duty. Other items which will get relief in import duty are polyester films imported for the manufacture of magnetic tapes, metallised plastic films imported for the manufacture of electronic capacitors, and sports goods imported for use in national or international competitions. The relief on all these items together will amount to Rs. 1.75 crores.

2.25. The auxiliary duties of customs levied hitherto are being continued upto the 30th June 1977 and the effective rate of this levy will remain unchanged.

2.26. Taking Union Excise duties and Customs duties together the yield for 1976-77 for the Centre will be Rs. 47.25 crores.

2.27. I am now left with only two proposals designed almost wholly to raise resources for the benefit of the States.

2.28. The rates of stamp duties levied on Instruments such as receipts and bills of exchange mentioned in the Union List have not been changed for a long time. With effect from 1st June 1976, I propose to raise the rates of stamp duties on certain items. The proposed changes in the rates of stamp duties are likely to yield an additional revenue of about Rs. 22.57 crores per annum. However, during the next financial year, the accrual of additional revenue to the States and to the Union would be of the order of Rs. 18.44 crores and Rs. 37 lakhs respectively, because the new rates of duty would be effective for only a part of the financial year.

2.29. Another change which I have proposed is the revision in rates of excise duties on medicinal and toilet preparations containing alcohol, narcotic drugs and narcotics as also an amendment of the definition of certain terms including narcotic drugs and narcotics. The State Governments have pointed out that while State excise duties on alcohol were raised, the duties of excise on the above medicinal and toilet preparations have not undergone any change since 1964, and this has led to misuse of these medicinal preparations. I, therefore propose to raise the rates of excise duties on medicinal and toilet preparations containing alcohol, narcotic drugs or narcotics so as to yield an additional revenue of about Rs. 7.5 to 8 crores per annum. Out of this amount, about Rs. 50 lakhs per annum will accrue to the Union in respect of Union territories and the balance to the States.

III

3.1. The net additional mobilisation of taxes as a result of the various measures I have outlined will be Rs. 48 crores for the Centre and Rs. 32 crores for the States. The Budgetary gap of Rs. 368 crores indicated earlier will therefore come down to Rs. 320 crores. I propose to leave this gap uncovered. It is my considered judgement that this order of deficit will not accentuate inflationary pressures in the economy. Nevertheless, there is an inherent element of unpredictability in the course of economic activity and we shall continue to keep close and vigilant watch over the economy.

3.2. There is a tide in the affairs of nations, as of men, which taken at the flood leads on to fortune. The nation is at the crest of such a tide. The economy is poised for a surge forward. The Emergency and the New Economic Programme have ushered in a qualitative change in the economic environment. We must now take advantage of the favourable factors and inject a new dynamism to programmes of economic and social development.

In framing these proposals, I have been guided by our cherished national goal, enunciated by the Father of the Nation, of ensuring sufficiency for all and superfluity for none.

Sir, in all humility, I now commend the Budget for the acceptance of this House.